बाढ़ 2008: अनकही कहानी

Pramod Ranjan

▶ **To cite this version:**

Pramod Ranjan. बाढ़ 2008: अनकही कहानी. 2008, ⟨10.17613/e7zr-7953⟩. ⟨hal-03939110⟩

HAL Id: hal-03939110

https://hal.science/hal-03939110

Submitted on 14 Jan 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial 4.0 International License

बाढ़ 2008

अनकही कहानी

11 सितंबर को अमेरिका में हवाई हमले में लगभग 5 हज़ार लोग मारे गये थे. आज भी उनकी याद में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं. भारतीय मीडिया भी इन तस्वीरों को प्रसारित करता है. क्या 18 अगस्त की याद में, जिसमें 5 हजार लोग मारे गये, भी मोमबत्तियां जलाई जाएंगी? क्या हमारा देश इसे एक काले दिन की तरह याद करेगा? उत्तर है-नहीं. कारण; हम-आप सब जानते हैं.

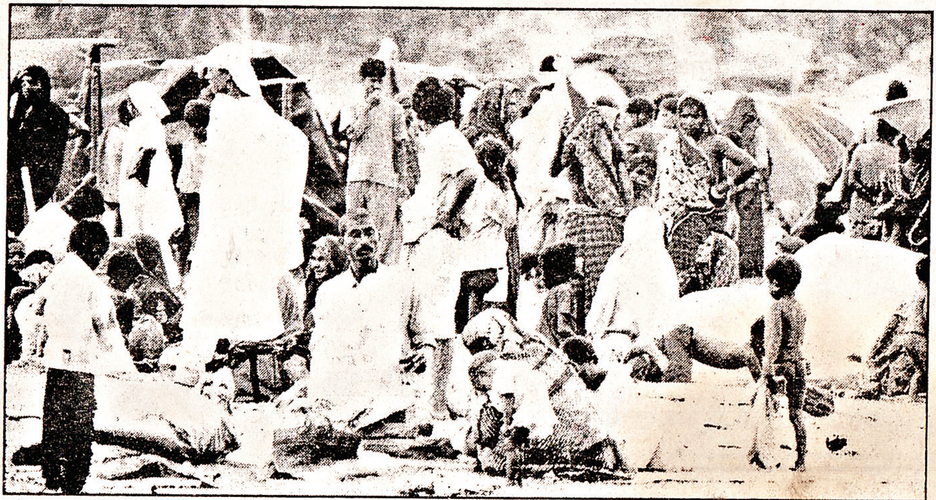

प्रमोद रंजन, सत्यकाम, अष्टावक्र, मेधा पाटकर, प्रभात कुमार शांडिल्य

मस्तक-कुंड में जलती
सत्-चित-वेदना-सच्चाई व गलती-
मस्तक शिराओं में तनाव दिन रात.

अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे
उठाने ही होंगे.
तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब.

- **मुक्तिबोध**

बाढ़ 2008

अनकही कहानी

'फ्री थिंकर्स'

की ओर से

15 सितंबर, 2008 को जारी

(दूसरा संस्करण : 25 सितंबर,2008)

मूल्य : 5 रुपये

http://sanshyatma.blogspot.com

कुम्हरार, पटना-800026
e-mail : gramprivesh@gmail.com

बाढ़ की जाति

प्रमोद रंजन

राज्य सत्ता की जाति

मैं जो कुछ बताने जा रहा हूं वह एकबारगी तो मुझे भी अविश्वसनीय लगा. ज्यों-ज्यों कड़ियां जुड़ती गयीं, तस्वीर साफ होती गयी. यह बाढ़ आयी नहीं, लाई गयी है. कुशहा तटबंध तोड़ा तो नहीं गया लेकिन उसे टूटने का भरपूर मौका दिया गया.. विपदा के बाद राहत कार्यों में सरकारी मशीनरी खुद ब खुद अक्षम साबित नहीं हुई, उसे अक्षम बनाये रखा गया. जातिवाद के लिए चर्चित बिहार में अंजाम दी गयी यह कथित लापरवाही, वास्तव में कम से कम आजाद भारत की सबसे बड़ी, सुव्यवस्थित जाति आधारित हिंसा है. वर्ष २००८ के १८ अगस्त को कासी क्षेत्र में आयी बाढ़ में सरकारी आकड़ों के अनुसार कम से कम २५ लाख लोग तबाह हुए हैं. एक पुख्ता अनुमान के अनुसार लगभग ५ हजार लोग मारे गये हैं.

कोसी अंचल के दलित जब बिल में पानी जाने के बाद बिलबिलाती चींटियों की तरह मर रहे थे; यादवों के पशु, घर, खेत सब कोसी की धार में बहे जा रहे थे-ऐसे समय में सत्ताधारी दल जनता यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने इन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही. जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद की सक्रियता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 'भाई का दर्द भाई ही समझता है'. प्रेस को जारी इस बयान में तिवारी ने कहा कि चूंकि इसके पहले आयी बाढ़ से सहरसा, मधेपुरा (यादव बहुल जिले) नहीं प्रभावित होते थे इसलिए लालू इतने सक्रिय नहीं होते थे. 'भाई' की पीड़ा ने उन्हें इतना संवदेनशील बना दिया है कि वे इसके बीच कूद पड़े हैं. इस फूहड़ बयान के निहितार्थ गंभीर हैं. यह सच है कि बाढ़ग्रस्त इलाका यादव बहुल है, इसके अलावा वहां

बड़ी आबादी अत्यंत पिछड़ों और दलितों की हैं. (सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के बाढ़ग्रस्त इलाकों से गुजरते हुए, राहत शिविरों में बातचीत करते हुए, मुझे महसूस हुआ कि यहां दलितों की आबादी भी बहुत ज्यादा है) लगभग ३० विधान सभा सीटों वाला बाढ़ से प्रभावित हुआ यह क्षेत्र लालू प्रसाद को बिहार की सत्ता में बनाये रखने का एक बड़ा कारण रहा था. लेकिन पिछली बार पासा पलट गया. कहते हैं कि उस समय इलाके के यादव लालू से नाराज हो गये थे. राष्ट्रीय जनता दल के एक कद्दावर नेता बताते हैं कि 'राजद को बिहार की सत्ता से बेदखल करने में बड़ी भूमिका इस क्षेत्र की रही'. पिछले विधान सभा चुनाव में इन जिलों की अधिकांश सीटें राजद हार गया. अभी इस क्षेत्र की कुल २८-३० सीटों में से २२-२३ विधायक जदयू अथवा भाजपा के हैं. इसके बावजूद राजग की ओर से यह बयान आया कि यादव होने के कारण लालू इस क्षेत्र के लिए चिंतित हैं. बयान बताता है कि इस विकराल आपदा के समय बिहार में सिर्फ घृणित राजनीति ही नहीं चल रही है. इसके पीछे जातिवाद की चरमावस्था है. ऐसा कुत्सित जातिवाद, जो यह हुंकार भरता फिर रहा है-यादवों, दलितों, अति पिछड़ों! तुम्हारे समर्थन का भी हमारे लिए कोई मोल नहीं है.

यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि बिहार में जाति-शत्रुओं के सफाये के लिए बाढ़ के रूप में सुव्यवस्थित हिंसा की नयी तकनीक लागू की गयी. इस तकनीक ने नरेंद्र मोदी के प्रयोगों को भी पीछे छोड़ दिया. नरेंद्र मोदी वंदे मातरम् गाने वालों को बख्श देने की बात करते हैं. लेकिन यहां लाखों लोग राज्य सत्ता को समर्थन देने के बावजूद सिर्फ इसलिए अपने हाल पर छोड़ दिये गये क्योंकि वे यादव थे, दलित थे. उन्होंने राजग को वोट किया था तो क्या, वे अवधिया कुरमी अथवा भूमिहार तो न थे. इसे नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्यसत्ता में आयी एक सवर्ण जाति की कुंठा के विस्फोट के रूप में भी देखा जा सकता है. लालू प्रसाद के शासन काल में यादवों के मातहत रहने का दंश उन्हें १७-१८ वर्षों से सता रहा था. उन्हें यह 'सुख' है कि कीड़े-मकोड़ों की तरह बिलबिलाओं सालों, देखते हैं, कौन क्या कर लेता है!

नेपाल में कुशहा के पास तटबंध टूटने की सूचना भीमनगर बैराज के पास तैनात मुख्य अभियंता सत्यनारायण ने नौ अगस्त को ही बिहार सरकार को दे दी थी. यह एक पूर्णतः प्रमाणित हो चुका तथ्य है, जिसका खुलासा इस इंजीनियर को डिमोट कर स्थानांतरित कर देने के बाद हुआ. इसके अलावा अन्य श्रोतों से भी तटबंध में रिसाव होने सूचना बिहार के सत्ताधीशों को थी. लेकिन इसे रोकने की कोशिश करने की बजाय तटबंध मरम्मती के नाम पर 'माल' बनाने की कोशिशें की जाती रहीं. परिणाम यह हुआ कि १८ अगस्त को तटबंध टूट गया. (कुछ लोग इसके टूटने की तारीख और पहले बताते हैं) पानी लाखों लोगों का आशियाना उजाड़ते, हजारों की जान लेते रोजाना नये इलाकों की ओर बढ़ता गया.

तटबंध टूटने से छूटे लगभग डेढ़ लाख क्यूसेक पानी से १८, १९ और २० अगस्त को जिन बस्तियों की सीधी टक्कर हुई, वे तो उसी समय नेस्तानाबूद हो गयीं. झुग्गी-झोपड़ियों, दलितों के टोलों में तो न कोई आशियाना बचा, न जानवर, न एक भी आदमी. अगले ७-८ दिनों तक पानी कोसी की नयी (मुख्य) धार के आसपास के गांवों की ओर बढ़ता गया. लोग अकबकाए चूहों की तरह, जिधर राह मिली, भागने लगे. सब ओर पानी ही पानी. रास्ते का अता-पता नहीं. कोसी की विकराल, हहराती, कुख्यात तेज धारा. डूब कर मरने वालों में-पैदल भाग रहे लोगों, केले के पेड़ों, लोहे ड्रामों, धान उसनने वाले कटौतों आदि का सहारा

लेकर निकलना चाह रहे लोगों की संख्या कितनी रही, यह हम कभी नहीं जान पाएंगे. कितनी निजी नौवें पलटीं, कितनों को स्थानीय अपराधियों ने पानी में फेंका, कितनी महिलाओं के जेवर छीने गये, कितनों ने अस्मत गंवायी. क्या कभी सामने आएगा इनका वास्तविक आंकड़ा?

उधर यादव-दलित डूबते जा रहे थे और इधर सत्ताधारी जनता दल युनाइटेड प्रधानमंत्री से मिलने के लिए ५०० पृष्ठों का दस्तावेज तैयार कर रहा था. लेकिन यह कागजात बाढ़ से संबंधित नहीं थे. यह कागजात थे रेलमंत्री द्वारा कुछ कट्ठा जमीनें लिखवा कर रेलवे की नौकरियां बांटने के. १८ अगस्त को तटबंध टूटने,सैकड़ों बस्तियों के बह जाने, हजारों लोगों के मारे जाने की सूचनाओं के बीच ६ दिन गुजारने के बाद-२३ अगस्त को-जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह व केसी त्यागी जब भाजपा के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बाल नकवी की अगुवाई में प्रधानमंत्री से मिले तो उनके सामने बाढ़ कोई मसला नहीं था. वे सिर्फ यह चाहते थे कि लालू प्रसाद को केंद्रीय मंत्रीमंडल से बाहर कर दिया जाए. मुख्यमंत्री ने बाढ़ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण पहले २० अगस्त को और फिर २४ अगस्त को किया. तब तक भारी तबाही हो चुकी थी. २० अगस्त को ही उन्होंने देखा पानी सैकड़ों बस्तियों को लीलता आगे बढ़ा जा रहा है. हजारों लोग मारे जा चुके हैं. लेकिन तब भी उनका ग्लेशियर सा हिंसक ठंडापन बरकरार रहा..बिना हो-हंगामे के जितना डूब सकें, डूबें हरामी! २४ अगस्त को हवाई अड्डा पर प्रेस कांफ्रेस में तथा २६ अगस्त को रेडियो से जनता के नाम 'संदेश' देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में प्रलय आ गया है. लोग दान देने के लिए आगे आएं. हजारों लोगों की मौत के बाद, बाढ़ के ६ वें दिन रेडियो पर मुख्यमंत्री द्वारा पढ़े गये इस संदेश की भाषा में 'भावुकता' कूट-कूट कर भरी गयी थी. मुख्यमंत्री ने अपील की कि लोग बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से बाहर निकलें. सरकार सब व्यवस्था करेगी!

जाहिर है, राज्य सरकार न सिर्फ तटबंध की सुरक्षा बल्कि बचाव-राहत कार्य में भी सुस्त बनी रही. सरकार के खैरख्वाह समाचार माध्यमों के माध्यम से अपना तीन साल पुराना तकिया कलाम दुहराते रहे कि यह सब कुछ पिछली सरकार का किया-धरा है. लालू ने तटबंध मरम्मती के लिए कुछ किया ही नहीं.

रेलकर्मी का जातिवाद

राज्य सत्ता ने ऐसा किया तो जाहिर है, यह अनायास नहीं रहा होगा. जाति बिहार के रग-रग में कूट-कूट कर भरी है.

बिहार में भारी तबाही की खबर सुनकर मेधा पाटकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचीं. उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मुंबई से लायी जा रही राहत सामग्री (कपड़ों से भरी ३१ बोरियां) एक रेल कर्मी उदयशंकर सिंह ने बरौनी स्टेशन पर फेंक दी. ये कार्यकर्ता मेधा के नेतृत्व में मुंबई की झुग्गी-झोपड़ी वासियों के हित में चलने वाले 'घर बचाओ' आंदोलन से जुड़े थे और नीची जातियों से आते थे. कार्यकर्ता लाल बाबू राय, अतीक अहमद, बाबुलाल और राजाराम पटवा ने इस संबंध में की गयी शिकायत में लिखा है कि 'सभी सामान फेंकने के बाद कैपिटल एक्सप्रेस के गार्ड उदयशंकर सिंह ने अभद्र गालियां देते हुए कहा कि कहां से दलित हरिजन का कपड़ा उठा कर ले आया है. ऐसा बोलते उसने सफाई कर्मचारी से डिब्बे में झाडू लगवाया. उसके

वाद गार्ड वॉक्स में रखे गोमूत्र एवं गंगाजल की शीशी निकाल कर गंगाजल एवं गोमूत्र का छिड़काव किया'.

मेधा पाटकर ने इस घटना की जानकारी मिलने के बाद इन पंक्तियों के लेखक से कहा कि वह इस सूचना से बेहद व्यथित हैं. विहार के जातिवाद के बारे में उन्होंने सुना तो था लेकिन यह आज के समय में भी इतना विकराल होगा, इनका अनुमान उन्हें न था. मेधा के चाहने पर एक समाचार पत्र में 'सामान फेंके जाने' की सूचना देती छोटी सी खबर छपी. लेकिन उसमें इस बात का जिक्र न था कि सामान क्यों फेंका गया. लालू प्रसाद ने मेधा को फोन किया और रेलवे के एक उच्चाधिकारी को उनसे माफी मांगने को कहा. गार्ड उमाशंकर सिंह सस्पेंड किया गया. जब लालू प्रसाद का फोन आया मेधा के साथ हम सुपौल जिला के छुरछुरिया धार के पास से लौट रहे थे. वहां सेना द्वारा चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के पास राहत सामग्री वितरित करते-हुए मेधा ने ३५-४० मौतें (सिर्फ उसी स्थान पर) रिकार्ड की थीं, जबकि उस समय तक राज्य सरकार बाढ़ में मरने वालों की कुल संख्या महज २५ बता रही थी. मेधा इस सबसे बेहद विचलित थीं. लालू प्रसाद ने भी उन्हें फोन पर बताया कि कम से कम ५० हजार लोग मरे हैं, सरकार लगातार झूठ बोल रही है. उनका कहना था कि नीतीश पुनर्निर्माण कार्य जनवरी-फरवरी तक शुरू करेंगे ताकि लोकसभा चुनाव में इसका लाभ ले सकें. मेधा ने लालू प्रसाद को कहा कि राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाने के बावजूद इसे लेकर अभी तक केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक नहीं हुई है. जबकि नियमानुसार, राष्ट्रीय आपदा को लेकर केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक तुरंत होनी चाहिए थी, जिसमें पीड़ित क्षेत्रों के कृषि-स्वास्थ आदि मसलों पर निर्णय लिया जाता.

यह सब ५ सितंबर की बात है. 'घर बचाओ' आंदोलन के कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार करने वाला सस्पेंड हो चुका था. ६ सितंबर को इससे संबंधित समाचार भी सभी अखबारों में छपा. लेकिन मेधा चाहतीं थीं कि उस रेलकर्मी का जातिवादी व्यवहार भी अखबारों के माध्यम से सामने आये. उन्होंने मुझसे कहा कि सामान फेंकने से बहुत ज्यादा गंभीर और धक्का पहुंचाने वाली वह जातिवदी प्रवृति है. इसे अखबारों को उठाना चाहिए.

लेकिन मेधा को बिहार की सवर्ण मीडिया की बारीक बुद्धि की जानकारी न थी. सिर्फ मेधा ही क्यों, मैं भी तो लगभग इससे अन्जान ही था, तभी तो इसके लिए असफल कोशिश की.

सत्ता विहीन सवर्णों का दु:ख

बाढ़ क्षेत्र के दौरा करते हुए मैं अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहरसा में एक कायस्थ परिवार का कंप्यूटर इस्तेमाल करता रहा था. इस परिवार का मधेपुरा स्थित घर डूब चुका है, सहरसा में वे किराये पर रहते हैं. उनके सभी पड़ोसियों के गांवों में स्थित पैतृक मकान डूबे थे. इनमें अधिकांश कायस्थ थे. इन सबके अनेक परिजन सहरसा में ही राहत शिविरों में आश्रय लिये थे. अपनी छोटे-छोटे किराये के कमरों में वे कितनों को जगह देते? रोजाना दिन भर बाढ़ पीड़ितों का इनके यहां आना-जाना लगा रहता था.

इनमें से कई परिवार ऐसे थे, जिनके मामा, चाचा, बहन या ससुराल के गांवों में लोग अब भी फंसे थे. उन्हें निकालने के लिए न कोई नाव पहुंच रही थी, न ही राहत सामग्री. वे चाहते थे कि मैं बतौर पत्रकार संबंधित जिले के जिलाधिकारी से बात कर उनके गांवों में नाव भिजवाने की व्यवस्था करूं. मैंने कोशिश भी की लेकिन

नतीजा सिफर रहा. ऐसा तो नहीं लगा कि संबंधित जिलाधिकारी ने जानबूझ कर उन गांवों में नाव नहीं भेजी; पर मेरी असफलता पर उन किरायेदारों की राय रोचक थी. उनका कहना था कि कुछ भी कर लीजिये हम फारवडों के लिए यह सरकार कुछ भी नहीं करेगी.

९/११ बनाम ८/१८

११ सितंबर को अमेरिका में हवाई हमले में लगभग ५ हजार लोग मारे गये थे. आज भी उनकी याद में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं. भारतीय मीडिया भी इन तस्वीरों को प्रसारित करता है. क्या १८ अगस्त की याद में, जिसमें ५ हजार लोग मारे गये, भी मोमबत्तियां जलाई जाएंगी? क्या हमारा देश इसे एक काले दिन की तरह याद करेगा? उत्तर है-नहीं. कारण; हम-आप सब जानते हैं.

और अंत में

आज १२ सितंबर की सुबह है. दो दिन पहले ही बाढ़ क्षेत्र से पटना लौट आया हूं. अखबार देख रहा हूं. कई अखबारों में ११ सितंबर को अमेरिका में जलाई गयी मोमबत्तियों और उस हमले में मारे गये लोगों के परिजनों की व्थाएं छपीं हैं. पटना से प्रकाशित हिंदुस्तान में एक खबर है. 'केमिकल से नष्ट होंगे पशुओं के शव : सुशील मोदी'. सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व बिहार के उपमुख्यमंत्री हैं. खबर इस प्रकार है-'उपमुख्यमंत्री ने बताया कि केमिकल की खेप गुजरात से चल चुकी है. इसके जरिए पशुओं के शवों को मिनटों में नष्ट किया जा सकता है. इससे बदबू और महामारी फैलने की आशंका नहीं रहेगी.. पहली बार राज्य सरकार की ओर से व्यवस्थित ढ़ंग से राहत कार्य चलाया जा रहा है'.

केमिकल, पशुओं के शव के लिए? और मनुष्यों के उन हजारों शवों के लिए क्या, जो झाड़ियों, बांसबाड़ियों व उंची मेड़ों के किनारे पड़े सड़ रहे हैं. बाढ़ आए लगभग एक माह होने को आ रहा है. राज्य सरकार की ओर से मनुष्यों के शवों की चिंता करता कोई बयान अभी तक नहीं आया है. सुशील मोदी बता रहे हैं कि केमिकल 'गुजरात' के आ रहा है.(और शायद 'आइडिया' भी). राज्य सरकार की ओर से पहली बार 'व्यवस्थित ढंग' से राहत कार्य चलाया जा रहा है. इसी केमिकल से व्यवस्थित ढ़ंग से आदमियों के शवों को भी 'मिनटों' में ठिकाने लगाया जाएगा. न बदबू होगी, न आक्रोश फैलेगा. आखिर कुछ समय बाद ही वहां कई हजार करोड़ रुपयों का पुनर्निर्माण कार्य करने जाना है... और, मनुष्य मरे भी कहां हैं? मरे तो शुद्र हैं. भाजपा जिस मनुवाद में विश्वास करती है उसके अनुसार शुद्र और पशु एक समान होते हैं.

बाढ़ है, मजाक नहीं

अष्टावक्र

इस बाढ़ में एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है कि क्या नालंदा जिला में बाढ़ आती तो नीतीश ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते? इसका जवाब तो नीतीश कुमार ही दे सकते हैं, लेकिन हकीकत है कि नीतीश सरकार ने सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिलों को जल-प्रलय में आराम से डूबने-उतराने दिया. जब वहां प्रलय दहाड़ मार रहा था तो पटना के एयरकंडीशन कमरों में शासक दल के असराफ नेता जाम से जाम टकरा रहे थे कि अहीरों का विनाश हो गया. मनोविज्ञानी फ्रायड ने कहा था कि हमारी क्रियाशीलता के पीछे अवचेतन शक्तियां होती हैं. संभव है नीतीश की लालू विरोधी अवचेतना अहीर विरोधी अवचेतना में तब्दील हो गयी हो. हिटलर के मामले में भी ऐसा ही हुआ था.

दरअसल, कोसी के बाढ़ प्रभावित इलाके में अहीरों की संख्या काफी है. इसके अलावा ज्यादातर अन्य पिछडी जातियां व दलित हैं. कुरमी-भूमिहार वहां न के बराबर हैं. इसलिए बिहार की कुरमी-भूमिहार सरकार ने अहीरों, अन्य पिछड़ों व दलितों को डुबा मारने में कोई कसर नहीं छोडी. बाढ़ से भाग कर जब लोग पटना आने लगे तो सरकारी मिशनरी उन्हें पीछे धकेलने लगी कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के राहत शिविरों में ही रहो. इधर आना मना है. नीतीश कुमार का कहना था कि पटना में आकर उन्हें ड्रामा नहीं करने दिया जाएगा. लेकिन जाने-अनजाने यह घटना हिटलर के गैस चैंबरों की याद दिलाती है कि कैसे उत्पीड़न से भाग रहे लोगों को गैस चैम्बरों में धकेल दिया जाता था. अंतर केवल यह था कि यहां गैस की जगह जल चैंबर थे.

लगभग चौथायी करोड़ लोग अभी जो पीड़ा झेल रहे हैं, उन्हें देखने के लिए न कोई पत्रकार है न नेता. तटबंध की टूट रोकने में अक्षम नीतीश सरकार ने समाचारों पर अच्छा तटबंध लगया है! समाचार पत्रों के पन्चानवे फीसदी पत्रकार उंची जातियों से आते हैं और उनमें से ज्यादतर नीतीश कुमार के इस फासिस्ट अभियान का हिस्सा बन चुके हैं. इनकी बदौलत नीतीश कुमार का अभिनव फासिज़्म नयी शकलें ले रहा है. हिटलर-मुसोलनी से ज्यादा सूझ-बूझ से नीतीश इसकी देख-रेख कर रहे हैं. इस नये फासिज़्म में यहूदी की जगह 'यादव' हैं. पटना के कुरमी-भुमिहार मिठाइयां बांट रहे हैं कि लालू की माई (ईशारा लालू के जाति समीकरण एम-वाई की तरफ है) इस बाढ़ में डूब चुकी है.

बाढ़ की विभीषिका बतलाकर नीतीश सरकार चंदा बटोरने में लगी है. राहत से ज्यादा उसे चंदे की चिंता है. हजार रुपये का चेक लेने के लिए भी वे स्वयम् ससमय हाजिर रहते हैं. प्रेमचंद की एक कहानी 'कफन' का स्मरण कीजिए. बुधिया की लाश पड़ी है और घीसू-माधव कफन के लिए चंदा कर रहे हैं. नीतीश कहते हैं कि उन क्षेत्रों में पुनर्निर्माण करेंगे. अरबों रुपये झोली में आ चुके हैं. हजार करोड़ तो प्रधानमंत्री ने ही दिये. फिर तो सिलसिला ही चल गया. सिलसिला जारी रहेगा. बाढ़ की बीहरी देर तक चलेगी.

बहुत माल आएगा. नालंदा-बेगुसराय के कुरमी-भूमिहार-ठेकेदार अभी से पांख तौल रहे हैं. अक्टूबर बाद कोसी क्षेत्र में जाना है. जै कोसी मैया की. जय नीतीश भैया की. आदमी नहीं कमाल है साहब. ऐड़ी

से मूंडी तक बुद्धि ही बुद्धि. पुरखों ने बेलछी में दलित दहन किया था-कुलवल्लभ ने कोसी में अहीर दहन कर दिया. कुरमी बुरबक नहीं होते कि दंगा-फसाद किया और मुआवजा पाने के लिए औलादों को छोड़ दिया. नगरनौसा में मियांमारी की तो नोआखाली को फेल कर दिया. साले पूत भी नहीं बचे. अब इन्हीं मियों के लिए इफ्तार कर रहे हैं. अभी तो भागलपुर का पाठ पढ़ा रहे हैं, अगले चुनाव में वोट नहीं दिया तो नगरनौसा का पाठ पढ़ा देंगे.

दहन-दहान-दनदनान. सब कुछ एजेंडे मे हैं. सब कुछ समय से होगा. हिटलर जिंदाबाद का नारा है, भावी इतिहास हमारा है. नीतीश कुमार हिटलर के अवतार हैं. दोनों राष्ट्रीय समाजवादी. दोनों को अपने मुल्क के अस्मिता की चिंता. दोनों विकास पुरुष. पुराने हिटलर ने जर्मनी में कहा था-गर्व से कहो हम जर्मन हैं. नये हिटलर ने बिहार में कहा है-गर्व से कहो हम बिहारी हैं. विकास की जो मिसाल हिटलर ने रखी थी, वही मिसाल नीतीश ने रखी है. उसने चुकंदर से चीनी निकाली थी, ये गन्ने से इथनॉल (पेट्रॉल) निकाल रहे हैं. पूरी पैरोडी है. गोयवेल्स भी है, इवा भी.

गैस चैंबर से चलकर जल चैंबर तक पहुंच चुके हैं. गैस में बहुत खरचा है, हाइड्रोपावर से कमाल करना है. इसे ही कहते हैं बुद्धि व्यापार. अभी यह व्यापार चलेगा. जब पुनर्निर्माण होगा तब लोग देखेंगे कि असल बाढ़ क्या है. जहां तक कोसी का फैलाव हुआ है, वहां तक कुरमी का फैलाव होगा. अहीरिस्तान बदलकर कुरमीस्तान हो जाएगा. तब लोग समझेंगे कि नीतीश किस चिड़िया का नाम है.

स्मृति-शून्यता के बीच जो याद रह पाया..

एक संवाददाता की डायरी

उस समय दस-ग्यारह साल का रहा होऊंगा जब कुछ शरारत करते छत से गिरकर हाथ टूटा था. कंपाउंड फ्रैक्चर. कुहनी के पास से हड्डी टूट कर मांस और चमड़ा चीरती बाहर निकल गयी थी. खून बलबला रहा था. लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे. लोग जुटे. मुझे अस्पताल ले जाया गया...इस घटना ने मुझे 'बहादुर' बना दिया. गांव-घर के लोग आज भी याद करते हैं कि उतने छुटपन में, उतनी बड़ी चोट, उतने भयानक दर्द के बावजूद मैं नहीं रोया था. लेकिन वास्तव में उसमें कोई बहादुरी नहीं थी. मैं कुहनी चीर बाहर निकली हड्डी और हरहर बहता खून देख रहा था, लेकिन दर्द का कोई अहसास नहीं था. आज इसका कारण जानता हूं, बहुत बड़ी चोट दर्द का अहसास मस्तिष्क तक पहुंचाने वाली शिराओं को संवेदनहीन बना देती हैं.

२ सितंबर,२००८ की सुबह सहरसा स्टेशन पर उतरते बचपन में गुजरे इस वाकये की सच्चाई का भान शिद्दत से हुआ. सामान्य तौर पर देखने पर वहां भयावह बाढ़ का संकेत मौजूद नहीं दिख रहा था. सिवाय इसके कि दो प्लेटफार्मों पर 'बाढ़ स्पेशल' ट्रेनें लगी थी. एक शायद सुपौल जा रही थी, दूसरी अमृतसर. जिस तरह की खबरों को पढ़-देख कर वहां पहुंचा था, उसके अनुसार, स्टेशन पर भारी विलाप होने का अनुमान कर रहा था. 'खबर' की तलाश में वहां टहलने लगा तो सिर्फ एक बुढ़िया रोती दिखायी दी. बाढ़ स्पेशल ट्रेनों पर सवार होने वाले अधिकांश मजदूर वर्ग के लग रहे थे. जैसे वे सहज भाव से 'कमाने' बाहर जा रहे हों, या कमा कर लौट रहे हों. औरतें टोलियों में यहां-वहां पसरी थीं. उस बूढ़ी महिला से बात की तो मालूम चला कि उसका परिवार सकुशल निकल आया है पर सारा सामान बह गया. उससे बात करते देख दो नवयुवक पास आ गये. उनसे मालूम हुआ कि बाढ़ की हालत अब भी कितनी भयावह है. लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार, रोते-कलपते लोग क्यों नहीं दिख रहे? बाढ़ को तबाही मचाते लगभग एक पखबाड़ा बीत चुका है. इस बीच इन्होंने जो मुसीबतें झेली हैं, जिस तरह जान की बाजी लगाकर यहां तक पहुंचे हैं, वह मेरे उस कुहनी टूटने के दर्द से सैकड़ों गुणा अधिक भयानक है. विलाप इनके लिए बहुत छोटी चीज हो गयी है.

७ दिन के दौरे में कई दर्जन भुगतभोगियों की दिल दहला देने वाली व्यथाएं सुनीं. उन सबमें एक बात समान थी कि 'विलाप' कहीं न था. जिसके साथ, जितना ज्यादा भयानक हादसा हुआ था, उसकी 'स्मृति शून्यता' उतनी ही ज्यादा थी. सुपौल के छुरछुरिया धार के पास मिले हशमत को तो यह भी याद करने में भी दिक्कत आ रही थी कि सेना के जवानों की क्रूरता की वजह से उसके परिवार के छह लोग मरे कि सात लोग.

इस रोज मैंने जो रिपोर्ट अपने अखबार को भेजी वह यह थी :

बाढ़ ने सुखाया आंखों का पानी

सहरसा : कहां हैं बाढ़ पीड़ित ? खचाखच भरे स्टेशन परिसर में न कोई चीख, न विलाप. एक जगह खूब लंबी लाइन लगी है, रेलवे मुफ्त खाना बांट रहा है. बाकी सबकुछ तो सामान्य लग रहा है! वास्तव में यह दृश्य ज्वालामुखी का है. कौन जानता है, कितना और कैसा लावा भीतर ही भीतर खौल रहा है.

सैलाब से किसी तरह जान बचा कर सहरसा स्टेशन पहुंच रहे अधिकांश मधेपुरा के मुरलीगंज व बिहारीगंज के हैं. इसके अलावा सुपौल और सहरसा के भी लोग पहुंच रहे हैं. कुछ टोलियां पूर्णियां जिला की भी हैं.

मधेपुरा जिला की आर्थिक रीढ़ कहे जाने वाले मुरलीगंज और कभी 'मिनी कलकत्ता' के नाम से चर्चित बिहारीगंज व इनके आसपास के गांवों में भारी तबाही हुई है. माल-जाल सब गया, कितने लोग मारे गये, इसके बारे में सरकार द्वारा दी जा रही सूचनाएं भयावह रूप से अविश्वसनीय हैं. मुरलीगंज के निकट बसे रहठा गांव से आई बाढ़ पीड़ितों की एक टोली में मलिया देवी, दायजी देवी, रीना देवी, अनीता देवी और मुकेश कुमार है. गांव से लगभग ५० लोगों का जत्था चला था. सहरसा स्टेशन बस यही पांच पहुंच सके हैं. बाकी कब-कहां बिछड़ गये, इन्हें पता भी नहीं चला. मलिया देवी बताती हैं कि रहठा से कंठ भर पानी में लगभग छह घंटे का पैदल सफर कर हम जानकीनगर पहुंचे. जानकीनगर से तीन बार ट्रेन बदलनी पड़ी. पूर्णिया कोर्ट, कटिहार और मानसी होते हुए तीन दिनों में सहरसा पहुंच सके हैं. आगे कहां जाना है, इसकी कोई योजना नहीं है. जहां यह फूटी किस्मत ले जाए!

मलिया की टोली बताती है कि रहठा से जानकीनगर का पैदल सफर बेहद भयावह था. आठ फुट लंबे बांस से पानी की थाह लेते हम किसी तरह चलते रहे. रास्ते में तैरती लगभग आधा दर्जन लाशें देखीं. एक केला बगान का दृश्य तो रोंगटे खडा करने वाला था. केले के पेडों से अटकी थीं २००-३०० लाशें. यह केला बगान दीनापट्टी रेलवे स्टेशन से महज एक-डेढ़ किलोमीटर पहले है.

बाढ़ पीड़ितों की टोलियां सहज भाव से अपनी व्यथाएं सुनाती हैं. आंखों की कोरों तक कुछ बूंदें आती हैं. लेकिन बाहर नहीं टपकती. मौत का तांडव देखते इन्होंने १५ दिन बिता दिये हैं. लाइन में लगकर रेलवे से मिल रहा मुफ्त खाना खाते, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बांटे जा रहे पुराने कपड़ों के लिए छीना-झपटी करते हुए आखिर बच भी कैसे सकता है आंखों में पानी?

हर वाक्य में खबर

सहरसा के राहत शिविरों, अस्पतालों में घूमता रहा. बाढ़ पीड़ितों द्वारा कहा गया हर वाक्य 'खबर' है. कितना लिखता? किसी ने केले के थम के सहारे प्रलय को पार करते हुए पत्नी को खो दिया तो किसी ने अपने बच्चों को. कोई किसी पड़ोसी की छत पर सैकड़ों लोगों के साथ १० दिनों तक भूखा रहा था तो किसी ने डायरिया से मरे अपने जिगर के टुकड़े को छत से नीचे पानी में फेंक दिया था. अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की भीड़ थी. किसी के गर्भ से हाथ निकाले बच्चा चार दिनों से पड़ा था तो कोई खून

से लथपथ अस्पताल के फर्श पर पड़ी थी. न उन्हें बिस्तर मिल रहा था, न ही दवाएं. नवजात बच्चे दम तोड़ रहे थे. जगह-जगह लगे राहत शिविरों में जिंदा रहने भर भोजन पाने के लिए लंबी लाइनें लगीं थीं: सहरसा शहर के व्यापारी राहत कार्यों में खुलकर सहयोग कर थे. इसके मुकाबले में 'सरकार' कहीं नहीं थी. जिन-जिन से मिला, उनमें से कम से कम आधे लोगों का कोई न कोई गायब था. अधिकांश जान हथेली पर रख कर यहां तक पहुंचे थे. निजी नाव वालों ने किसी से ५०० रुपये प्रति आदमी वसूले थे तो किसी की बची-खुची सारी संपत्ति पानी में नाव पलट देने का भय दिखा कर ऐंठ ली थी. रहठा की रीना बेगम के बच्चे और पति को नाव वाले ने नदी में फेंक दिया. नेशनल एलायंस ऑफ पीपुल्स मुवमेंट के विजय कुमार बातते हैं कि यह अभागी महिला अभी पूर्णिया के खुश्कीबाग धर्मशाला में चल रहे राहत शिविर में रह रही है. सरकारी नाव वाले भी तेल के लिए पैसे ऐंठ रहे थे. हर किसी के गांव में अब भी सैकड़ो लोग नाव के इंतजार में फंसे थे. राहत सामग्री के नाम पर उन तक कुछ नहीं पहुंच रहा था. एयर ड्रॉपिंग से कहीं-कहीं कुछ गिरा था, लेकिन वह एकदम नाकाफी था. कई वाकये ऐसे मिले कि हेलीकॉप्टर से पानी में गिरा चूड़ा का पैकेट उठाने के लिए, जो धारा में उतरा, उसे उफनती कोसी अपने साथ ले गयी.

हिंदुत्ववादी संगठनों की सक्रियता

सहरसा में हिंदुत्ववादी संगठनों के सक्रियता साफ दिख रही है. विभिन्न नामों से इनके कई राहत शिविर चल रहे हैं. आपदा प्रबंधन की सहरसा शाखा के रेकर्ड के अनुसार शहर में कुल २३ राहत शिविर चल रहे हैं. इनमें से ८ जिला प्रशासन द्वारा संचालित हैं जबकि ६ हिंदुत्वादी संगठनों सेवा भारती, विद्यार्थी परिषद आदि द्वारा. हत्या के आरोप में जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन तथा निर्दलीय विधायक किशोर कुमार मुन्ना द्वारा एक-एक शिविर चलाया जा रहा है. इसके अलावा मारवाड़ी युवा मंच, ड्रग एसोसिएन आदि के शिविर हैं. जिला स्कूल में सेवा भारती द्वारा चलाये जा रहे राहत शिविर में भाजपा के स्थानीय विधायक संजीव कुमार झा मिलते हैं. उनके साथ पटना से आये भाजपा नेता हरेंद्र प्रताप भी हैं. बातचीत शुरू होती है तो हरेंद्र कहते हैं कि यहां ईसाई मिशनरियों की दाल नहीं गलने दी जाएगी. आरएसएस की पहल पर बाबा रामदेव से बात हो गयी है. जितने भी बच्चे अनाथ हुए हैं, वह सबको गोद लेंगे. पटना में सभी अखबारों को यह सूचना भेज दी गयी है. इस शिविर में मौजूद लोग बताते हैं कि अन्य शिविरों के मुकाबले यहां व्यवस्था अच्छी है. खाना ठीक मिल रहा. नाश्ता और दूध भी. कपड़े भी बांटे गये हैं.

यह सब सुनकर मुझे हैरत नहीं होती. आखिर आएएसएस जिंदा ही है इन्हीं हथकंडों के कारण. मेरा ध्यान तो रामदेव पर अटका है. बाबा रामदेव माने रामदेव यादव. वैसे ही जैसे लालू प्रसाद माने लालू यादव? सब जानते हैं यह इलाका यादव बहुल है. जाति इस देश की कितनी बड़ी सच्चाई है?

स्थानीय लोग बताते हैं भाजपा और जदयू के अधिकांश विधायक अपने घरों में दुबके हैं. राहत कार्यो के दौरान उन्हें भारी विरोध झेलना पड़ सकता है. और कहीं जल संसाधन मंत्री विजेंद्र यादव किसी भीड़ में पकड़े गये तो पूछिये मत कि क्या होगा. चाहे पुलिस कितनी भी गोलियां चलाए, लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं. दो निर्दलीय विधायकों-सहरसा के सोनबरसा क्षेत्र में किशोर कुमार मुन्ना और सुपौल के राघोपुर में नीरज कुमार बब्लू के राहत कार्यों की लोग तारीफ करते हैं. ये दोनों विधायक 'बाहुबली' हैं.

रामपुर टपरा

इसी सबके बीच मेधा पाटकर मिलीं. उनकी सादगी, मेहनत और सेवा भाव का मुझ पर जो प्रभाव पड़ा उसका जिक्र करने का समय यह नही हैं. मेधाजी के साथ मेरी पहली यात्रा पानी और बाढ़ पर लंबे समय से काम करते रहे रंजीवजी के सौजन्य से मधेपुरा होते हुए रामपुर टपरा तक की रही. जिस जीप से हम दौरा करते रहे वह वीपी मंडल के परिवार के तीसरे पीढ़ी के सदस्य (पौत्र) आनंद मंडल की थी. बाढ़ से इनका परिवार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है. घर डूबा हुआ है. आनंद सारथी की तरह लगातार हमारे साथ बने रहे.

मधेपुरा शहर में पानी भरा था. हमें बताया गया कि कई मोहल्लों में नावें चल रही हैं. अधिकांश दुकानें बंद थीं. बंद दुकानों के बीच शराब की दुकानों को खुला देखना हममें से कुछ को आश्चर्यचकित कर रहा था. लेकिन मुझे नहीं. पता नहीं क्यों उस समय मुझे गालिब याद आ रहे थे 'हुआ जब गम से यों बेहिस तो गम क्या सर के कटने का !' कोई सीधा प्रसंग न था, पर गालिब और उनके साथ-साथ नागार्जुन भी याद आते रहे. '९८ झोपड़ियों के बीच दो मकान'- इसी भाव की एक पंक्ति है उनकी. इसी मिथिलांचल में रचे-बसे थे बाबा. और रेणु की परती परिकथा भी. पूर्णियां की तरफ भी जाने की इच्छा हुई. अररिया में बहुत बर्बादी हुई है.

रामपुर टपरा पहुंचते-पहुंचते अंधेरा घिर आया. इसके आगे पानी का साम्राज्य है. यहीं से सेना और राज्य सरकार द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था. वहां एक जगह थी, जिसे वे लोग 'नहर' कह रहे थे. शायद यह नहर का तटबंध है. हजारों परिवार उस तटबंध पर आश्रय लिये थे. उन्हें न खाना मिल रहा था, न पीने का पानी. कोसी के पानी में सांप बहुत रहते हैं. रात में रोशनी की कोई व्यवस्था न थी. नाव वालों द्वारा लूट-पाट किये जाने की अनेक शिकायतें थीं. आगे कई गांव थे, जहां कोसी की तेज धारा के कारण नाव जा ही नहीं सकती. उन गांवों में दसियों हजार लोग भूख-प्यास से तड़प रहे होंगे. सेना के जवानों ने बताया कि उन गांवों से लोगों को निकालने के लिए एयर लिफ्टिंग के अलावा कोई चारा नहीं है. लेकिन एयर लिफ्टिंग के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं हैं. लोग मेधा पाटकर को पहचान नहीं रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि यह कोई महिला पत्रकार है. थोड़ी देर बाद वहां मधेपुरा के स्पेशल डीएम और एसपी पहुंचे. स्पेशल डीएम युवा और संवेदनशील हैं. लेकिन एसपी एक नंबर का काईंया. वह और उसके सिपाही हमसे शिकायत करने वालों को हमारे सामने ही धमकाते रहे.

मेधा रामपुर टपरा दूसरे दिन भी गयीं. चूड़ा और चीनी का पैकेट लेकर. मैं अपनी रिपोर्टें भेजने के लिए बेस कैंप (खादी ग्रामोद्योग भवन, सहरसा) में ही रूक गया. शाम को लौटीं तो मालूम चला कि बाढ़-पीड़ितों ने आज उन्हें पत्रकार की बजाए 'सरकारी आदमी' समझा. चूड़ा-चीनी कम पड़ा तो वे भूख से तड़पते लोगों द्वारा घेर ली गयीं. 'जब तक हमें नहीं मिलेगा, जाने नहीं देंगे!'

रूबी यादव

इस बीच, सहरसा के सदर अस्पताल की भी याद आ रही है. मेधा के साथ हम वहां पहुंचे थे तो रूबी यादव नाम की एक सद्यप्रसूता खून से लथपथ कराह रही थी. हमारे आने से थोड़ी देर पहले ही उसे बेड दिया था. उससे पहले की दो रातें उसने अपने ही खून में सने अस्पताल के फर्श पर बितायी थी. नवजात

बच्चा मर चुका था. पति बाहर कमाने गया हुआ था. टीवी के मरीज ससुर उसे किसी तरह पानी से घिरे गांव से बाहर निकाल लाये थे. अस्पताल प्रशासन न उसे दवाएं दे रहा था, न अन्य सुविधाएं. मेधा ने वहां सिविल सर्जन से हुज्जत करते करीब दो घंटे गुजारे. इस दो घंटे का नतीजा यह निकला कि अस्पताल प्रशासन ने उसके द्वारा खरीदी गयी १७०० रुपये की दवाओं में से ३०० रुपये का भुगतान रोगी कल्याण समिति से कर दिया. शेष राशि की रसीदें उसे दुकान वाले ने दी ही नहीं थी. मेधा की सिविल सर्जन से कही बात भी याद रह गयी है. मेधा ने कहा था 'शर्म नहीं आती आप लोगों को. आप इनकी सेवा के लिए ही इतनी मोटी पगार लेते है. मैंने आज तक किसी ससुर को अपनी पतोहु की ऐसी सेवा करते नहीं देखा, आपने देखा है? कम से कम इन्हें देख तो आप लोगों की इंसानियत जागनी चाहिए.' अस्पताल प्रशासन ने रूबी को पटना रेफर करने का वायदा किया था. बाद में उसका क्या हुआ, मैं जान नहीं पाया. मेधा लगातार उसकी चिंता कर रही थीं.

छुरछुरिया धार

५ सितंबर को छुरछुरिया धार पहुंचने पर मालूम हुआ कि मेरी अधिकतम कल्पना भी तबाही का जो अनुमान कर रही थी, वह वास्तविकता से बहुत कम था. निर्माणाधीन एनएच (संख्या संभवतः १०६) के किनारे-किनारे कई किलोमीटर तक दलित बांस की फट्टियां बांध रहे थे. कोई उस पर चादर लपेट रहा था तो कोई फटे पोलिथिन बैगों को एक-दूसरे से जोड़ कर अपने आशियाने को ढंकने का प्रयास कर रहा था. 'यह दलित राहत शिविरों में क्यों नहीं जाते?' मेधा के साथ जीप मे बैठे एक 'क्रांतिकारी' साथी ने जबाव दिया 'इनमें एक सांथ रहने की प्रवृति होती है. ये यहीं रहेंगे. राहत शिविरों में जाना ही नहीं चाहेंगे.' मैं उनकी समझ पर तरस ही खा सकता था. यहां बारिश में, कोसी के सांपों के बीच रहना इनकी 'प्रवृत्ति' है? यही प्रवृति यादव व अन्य ओबीसी जातियों में या खुद आपकी जाति में क्यों नहीं है? वास्तविकता यह थी कि इनमें से अधिकांश को न राहत शिविरों की जानकारी थी, न यह विश्वास कि ऐसी कोई जगह हो सकती है, जहां उन्हें गैर अछूत जातियों के साथ रहने दिया जा सकता है.. (बाद में मैंने सहरसा के एक राहत शिविर में रात गुजारी तो वहां अनेक दलित परिवार भी मिले)

छुरछुरिया धार का माजरा रूह कंपा देने वाला था. सेना का रेस्क्यू आपरेशन चल रहा है. कोसी की बलखाती धारा के बीच से औरत-मर्दों से पटी नावें चली आ रहीं हैं. हर नाव में ५०-६० लोग हैं. हाहाकार मचा है. वहां से निकटतम राहत शिविर करीब २० किलोमीटर दूर है. १४-१५ दिनों से भूखे लोगों को वहां पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं. न ही उस रूट में बसें चल रही हैं.

सेना की हर नाव से उतरने वाला कोई न कोई बेहोश हो जा रहा है. किसी को डायरिया तो किसी को पीलिया. असली बीमारी तो भूख है. कुछ स्वयंसेवी संगठन राहत सामग्री बांट रहे हैं. मेधा प्लास्टिक शीट्स ले कर आयी हैं. इन सबके लिए गिड़गिड़ता सैकड़ों लोगों का हुजूम.

एक महिला मिलती है. कुछ बोल नहीं पा रही है. क्या हुआ? 'बउआ पलर..' माने? मालूम चलता है वह उस पतियाही गांव के पास से, केले के थम की 'नाव' बना निकली थी, जहां इतनी तेज धारा है कि सेना

के नावों को भी नाकों चने चबाने पड़ते हैं. रास्ते में केले का थम कई बार पलटा. मां ने खुद को और बच्चों को रस्सी से बांध रखा था. बार-बार पलटने से रस्सी के बंधन ढीले होते गये. इस बार केले का थम पलटा तो चार और छह साल के उसके लालों को रस्सी रोके न रख सकी. मां की गोद से छूटते कोसी की लपलपाती जीभ उन्हें निगल गई. लेकिन इस मां को अपनी आंखों देखी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है. वह उस केले के थम को खोजने की बात करती है. उसे लग रहा है, उसके बच्चे अभी भी उससे बंधे होंगे. इस महिला का पति कमाने परदेश गया हुआ है.

यह आदमी बहुत बेचैन है. हमारी सक्रियता देख वह नजदीक आता है. १७ लोग मरे हैं सर, १७ लोग. कोई मेरी बात का विश्वास ही नहीं करता. १२ गांव में मरे,जबकि ५ ने पानी के पार आकर अस्पताल ले जाने के रास्ते में दम तोड़ दिया. यह भी पतियाही के पास के ही किसी गांव का है. अपने टोले में नाव भिजवाने की गुहार लगा रहा है. जो लोग पानी में फंसे हैं गांवों में, भूख बीमारी और भय से मर रहे हैं, उनकी लाशों को वहीं पानी में बहा दिया जा रहा है. यह बात, अपने परिजनों की लाशों को बहाने वाले कई लोगों ने बतायी. साफ है इसके अलावा चारों ओर से जानलेवा धाराओं से घिरे गांवों में कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है.

इसी छुरछुरिया धार के पास हशमत मिला. जिसके बारे में एक रिपोर्ट मैंने भेजी :

व्यथाएं, जो शब्दों में नहीं समातीं

सुपौल : कोसी के बाढ़ पीडितों की कथा वहां से शुरू होती है जहां से शब्दों की अभिव्यक्ति की क्षमता चूकने लगती है. न ही अपने परिवार के छह सदस्यों को खो देने वाले मोहम्मद हशमत की व्यथा के लिए 'व्यथा' शब्द पर्याप्त लगता है. न ही नाव पलटने के बाद गर्भवती पत्नी-बच्चों के लिए बिलखते हशमत को पीटने के बाद कोसी की अथाह धारा के बीच छोड़ देने वाले सैनिकों की क्रूरता के लिए 'क्रूरता'.

छुरछुरिया धार की चपेट आये ललितग्राम टेंगरी में १२-१३ दिन भूखे रहने के बाद २ सितंबर को मोहम्मद हशमत के परिवार को गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ सेना की दो नाव नसीब हो सकी. अफरातफरी के महौल में सैनिकों ने हशमत को एक नाव पर सवार किया, जबकि उसकी गर्भवती पत्नी शहरा खातून, विधवा भाभी अलेरून व उनकी दो किशोर उम्र की बेटियां जन्नत, तब्बसुम व बेटा दिलशाद, एक और भाभी साबिया को उनके बेटे इमाम तथा साला जफरूद्दीन को चार माह के बेटे मस्तकीन के साथ दूसरी नाव पर चढ़ा दिया. नाव तेज धारा में पहुंची तो इलाके के भूगोल से अपरिचित सैनिक नावों को वहां से गुजरती रेलवे लाइन के पास बने कलभर्ट की ओर ले कर चले गये. हशमत ने चिल्ला-चिल्ला कर उन्हें उस ओर जाने से मना किया, लेकिन उन्होंने उसे डांट कर चुप करवा दिया. कलभर्ट से टकराते ही आगे चल रही हशमत की पत्नी वाली नाव पलट गयी. पत्नी, दोनों भाभियां, साला उनके बच्चे सबके-सब डूबने लगे. सैनिकों ने उन्हें बचाने की कोई कोशिश न की. हशमत की ही कोशिशों से बह कर दूसरी नाव के पास आयी भाभी साबिया और दिलशाद को किसी तरह बचाया जा सका. घटना में हशमत के परिवार के छह लोगों के अलावा ललितग्राम टेंगरी गांव के ही दो बच्चों (कुल-८ लोगों) की मौत हो गयी. कथा के इस बिंदु तक तो हम हशमत के साथ हुई घटना को 'त्रासदी' और सैनिकों के कृत्य को 'क्रूरता' कह सकते

हैं. लेकिन इसके आगे की घटनाओं को क्या कहेंगे?

अपनों की लाशों को कोसी में बहते देख बौखलाए हशमत ने जब इसके लिए सैनिकों को कोसा तो उन्होंने उसे इतना मारा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा. लात-घूसों से जमकर पिटाई करने के बाद सैनिकों ने हशमत, जफरूद्दीन व दिलाशाद को कोसी की हहराती धारा के बीच लक्ष्मीपुर लाइन के पास ही भूखों मरने के लिए नाव से उतार दिया. हशमत किनारे कैसे पहुंचा, यह बताने में कथा बहुत लंबी हो जाएगी. यहां सिर्फ इतना बताना आवश्यक है कि सैनिकों ने लौट कर ८ लोगों की मौत की इस घटना की रिपोर्ट तक नहीं की. शुक्रवार (५ सितंबर) को छुरछुरिया धार पर चल रहे बचाव कार्य का समाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर के साथ जायजा लेने गये इस संवाददाता को हशमत पथराई आंखों से धार के किनारे-किनारे अपने परिजनों की लाशें ढूंढ़ता मिला. उसने बताया कि वे सैनिक यहीं हैं. हमने खोजना शुरू किया तो वे सैनिक गायब हो गये. वहां मौजूद सेना के उच्चाधिकारियों ने इस बारे में कोई जानकारी देने से इंकार कर दिया. बचाव कार्य पर तैनात एसडीपीओ शैशव यादव ने शनिवार (६ सितंबर) को हशमत का पूरी घटना का ब्योरा देता बयान तो राघोपुर थाना में दर्ज करवा दिया है. लेकिन क्या इससे हशमत को न्याय मिल पाएगा.? और हशमत एक हों तब न! कोसी धार में पिछले लगभग २० दिनों से ऐसे हजारों हशमतों की कथाएं तैर रहीं हैं, जिनके मर्म तक शब्दों के सहारे नहीं पहुंचा जा सकता.

कीड़े-मकोड़ों की तरह बहे दलित

छुछुरिया धार पर उस रोज तैनात एसडीपीओ शैशव यादव की इंसानियत अद्भुत थी. मेधा के साथ-साथ बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे एक स्वतंत्र पत्रकार पुष्पराज ने अनुसार, शैशव ने उन्हें बताया कि उनके उच्चाधिकारी ने उन्हें बाढ़ ड्यूटी में भेजते हुए सावधान किया था कि बच कर रहना, बौखलायी भीड़ कभी भी हमला कर सकती है. लेकिन शैशव तो किसी और ही मिट्टी के बने थे. उनके जमीर को यह गवारा नहीं था कि वह भूखों की भीड़ में राहत कार्य के लिए सर्विस रिवाल्वर लेकर जाएं. वह आज भी बिना सर्विस रिवाल्वर के ही ड्यूटी कर रहे थे. और पूरी तन्मया के साथ लोगों के दुःख-दर्द में शामिल थे. भ्रष्टाचारी, उचक्के और पत्थरदिल दर्जनों अधिकारियों से मिलने के बाद शैशव को देखना सुखद था.

वहीं हमें यह भी मालूम हुआ कि तटबंध टूटने के बाद पानी कितने वेग से आया था. पक्के मकान वाले तो किसी तरह बच गये, लेकिन कच्चे मकान वालों को कोसी की नयी धारा मकान के साथ बहा ले गयी. पक्के मकान वाले एक प्रत्यक्षदर्शी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पानी आया तो वे छत पर भागे. उनके घर के एक ओर ७०-८० घरों का दलित टोला था. छत से देखा, ७-८ फुट ऊंची विशाल जलराशि में दलितों की झोपडियां, ढोर, आदमी सब के सब कीड़े-मकौड़ों की तरह बहे जा रहे हैं. महज कुछ ही पलों में उस दलित टोला का नामो-निशान खत्म हो गया.

राहत शिविर की रात

८ सितंबर की रात किसी राहत शिविर गुजारने का फैसला कर करीब १०.३० बजे जिला प्रशासन द्वारा अल्पसंख्यक छात्रावास, सहरसा में चलाए जा रहे शिविर में पहुंचा. अधिकांश का भोजन हो चुका है. सब

सोने की तैयारी में हैं. यह शिविर खाली-खाली सा है. सब सरकारी शिविरों का यही हाल है. संस्थाओं, संगठनों, व्यवसायियों द्वारा चलाये जा रहे शिविरों में लोग ठसाठस भरे हैं. धबौली से आयी सरिता देवी कहती हैं वहां खाना अच्छा मिलता है, लेकिन जगह नहीं है. यहां हम मर्द-औरत (पति-पत्नी) को यह कमरा मिल गया है. जयपाल पट्टी की समतोलिया देवी, गुड़िया देवी समेत मड़वाहा, पचगछिया आदि से आयी लगभग सभी महिलाएं शिकायत करती हैं कि पिछले दस दिनों से यहां सिर्फ भात मिल रहा है. दाल पानी सी होती है. सब्जी नहीं मिलती. कभी चोखा तो कभी चटनी मिलती है. सब्जी नहीं. वे रोटी के लिए तरस रही हैं. मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड के बरकुड़वा की बबिता देवी बताती हैं कि उनका पूरा गांव खत्म हो गया. परिवार के लोगों का कुछ पता नहीं लग रहा. जब पानी आया तो बबिता अपने पति सुरेश यादव व बच्चों के साथ कुमारखंड में थी. सुरेश डाक विभाग विभाग के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हैं. पानी कुमारखंड में भी आया, लेकिन ये किसी तरह बच निकले. बरकुड़वा कुमारखंड से चार किलोमीटर पश्चिम रउता पुल के पास है. उसके आसपास के हरिबोला, टेंगराहा (पूर्वी) और राउत गाँव भी पूरी तरह साफ हो गये हैं. यादव, मुसहर, मोची, बांतर आदि जातियों की बहुलता वाले इन गांवों में ९५ फीसदी मकान कच्चे-झोपड़ीनुमा थे. बबिता रूआंसा होकर कहती हैं-सब जगह से सूचना मिल रही है कि इन गांवों में कोई नहीं बचा है. २० दिन से ज्यादा होने को आए, कोई बचता तो कहीं न कहीं किसी न किसी राहत शिविर में किसी को तो मिलता.

शिविर के और लोग मिलते हैं, सबकी बेचैनी एक सी है. अपनों का अता-पता नहीं लग रहा. एक महिला अचानक आकर जोर-जोर से कुछ कहने लगती है. वह और उसके बच्चे तो निकल आए हैं लेकिन चारों बकरियां बह गयीं. वह पूछ रही है कि क्या सरकार इसका कुछ देगी. जोर-जोर से बोलने से मना करने पर वह सिसकने लगती है.

कई बच्चे बीमार हैं. कई महिलाएं गर्भवती हैं. एक महिला की तो आवाज ही गायब हो गयी है. डॉक्टर आते हैं. दवाईयां भी मिलती हैं. लेकिन कई दिन की भूख झेल कर यहां तक पहुंची गर्भवती महिलाओं को न तो पौष्टिक आहर, न ही किसी प्रकार के टॉनिक देने का प्रावधान किया गया है.

रात गहराती जा रही है. मैं कमरा-दर कमरा झांकता चल रहा हूं. अधिकांश कमरों में बल्व नहीं है. तीन चार छोटे कमरों में पति-पत्नी सोये मिलते हैं. बड़े हॉलों में बच्चे, महिलाएं, किशोरियां भरी हैं. एक किशोरी का अधोभाग निर्वस्त्र है. वह शायद बोरी ओढ़ कर सोयी थी. बोरी हट गयी है. कुछ महिलाएं इससे भी बुरी अवस्था में दिखती हैं. शिविर दो होमगार्डों के हवाले है. बुजुर्ग गार्ड लखन मंडल बताता है कि अधिकांश महिलाओं के पास बदन पर पहने कपड़ों के अलावा दूसरा वस्त्र नहीं है. शायद उन्होंने रात में सोने से पहले उन्हें धो दिया है. सुबह पहनेंगी. आगे के कमरों में झांकने की हिम्मत नहीं होती.

यहां महिलाएं ही महिलाएं हैं. पुरुष कहां गये? बाढ़ के बाद अधिकांश कमाने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दमन आदि की ओर निकल गये हैं. कुछ संपत्ति की रक्षा के लिए पानी में डूबे गांवो में लौट गये हैं. सिर्फ इस शिविर में ही नहीं, जिन-जिन शिविरों में मैं गया वहां ७०-७५ प्रतिशत संख्या महिलाओं और बच्चों की थी. पुरुषों के अभाव में बूढ़ी-पुरनियों पर कई परिवारों की युवा महिलाओं की 'देखरेख' की जिम्मेवारी है. वे जानती हैं कि विपदा के इस समय में तरह-तरह के सौदागर घूम रहे हैं.यह कहना कठिन है कि इन्हें कब

तक राहत शिविरों में रहना होगा. या यह भी कि सरकार कब तक राहत शिविर चलाएगी. कच्चे घर वालों का तो सब कुछ तबाह हो गया है. पानी उतरने के बाद खेत भी बालू से भरे होंगे.

गार्ड कहता है आपके लिए मसहरी और दरी की व्यवस्था कर सकता हूं. चाहें तो सो जाएं. वह मुझे भला आदमी लगता है. बताता है कि इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए वह पूरी रात नहीं सोता. कहता है जब से यहां आया हूं नींद ही नहीं आती. छात्रावास परिसर में शौचालय नहीं है. पेट खराब होने की शिकायतें आम हैं. महिलाएं रात भर बाहर खुले में शौच के लिए जाती रहती हैं. ऐसे में मेन गेट बंद करना संभव नहीं है और असमाजिक तत्वों के भय से इसे खुला छोड़ नहीं सकता. वह मसहरी लाने जाता है तो मैं भी पीछे हो लेता हूं. यह शिविर का अस्थाई किचेन है. एक कोने में तीन रजिस्टर रखे हैं. ये शिविर में भोजन आदि पर होने वाले खर्च का हिसाब रखने के लिए हैं. तीनों की पृष्ठ संख्या अंचलाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित की गयी है. लेकिन शिविर शुरू होने के ८-१० दिन बीतने के बाद भी इसके पृष्ठ सादे हैं. सामानों की खरीद का हिसांब वहीं रखी एक दूसरी डायरी में लिखा गया है. बाद में इसे 'हिसाब-किताब' लगाकर अभिप्रमाणित रजिस्टरों में दर्ज कर दिया जाएगा.

दरी बिछ गयी है. थोड़ी देर लेटता हूं. सो कर क्या करूंगा...बस एक घंटा बाकी है. सुबह की पहली ट्रेन से मुझे भी उस पटना नगरी में लौटना है, जंहा सत्ताधीश बाढ़-पीड़ितों के लिए राहत-शिविर चलने नहीं देना चाहती.

नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री **मेधा पाटकर** ने लगभग १० दिनों तक बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया. इस दौरान ३ सितंबर को उनसे एक समाचपत्र के लिए यह छोटी सी बातचीत की गयी :

सरकारी मिशनरी में राहत कार्यों को लेकर उत्साह नहीं

- क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार राहत कार्यों में विफल हुई है?

मेघा : जो काम हुआ है वह बहुत कम है. आपसी तालमेल, विभिन्न सरकार एजेंसियों के राहत कार्यों में तालमेल का अभाव साफ दिखता है. मैनेजमेंट की कमी है. प्रशासनिक अधिकारियों में राहत कार्यों को लेकर उत्साह नहीं है. न पानी में फंसे लोगों को निकालने में तत्परता दिखायी पडती है, न ही राहत सामग्रियों को पहुंचाने में. लाखों लोग बेघर हो गये हैं. हजारों अभी भी पानी में फंसे हैं. आज की स्थिति में लोगों को बाहर निकालने में जो देर हो रही है, वह अक्षम्य है. बिहार की मेहनतकश जनता पर ज़ो गुजर रही है. उससे मेरा दिल दहल गया है. रानीगंज में सैकडों बहनें, बूढे-बच्चे केवल १०० मीटर की दूरी पार न करवाए जाने कारण भूखे पडे रहे. मुरलीगंज से भी लोगों को निकालने का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है. इन सब बातों को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है. देश भर से अधिक से अधिक बोटें क्यों नहीं मंगवाई जा रही? जो बोटें हैं भी, उनका सही उपयोग नहीं किया जा रहा. राज्य सरक. द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन की सही दूरी, विस्तृत नक्शा व जानकार गाइड नहीं दिये जाने कारण नौसेना की उपलब्ध ४५ बोटों में सिर्फ १५ ही सक्रिय हैं. मुरलीगंज के दक्षिण और उत्तर दोनों छोरों को मिलाकर दिन भर में महज ४००-५०० लोगों को ही निकाला जा रहा है. ऐसे अनेक गांव हैं, जो पिछले १७-१८ दिनों से डूबे हैं लेकिन उन गांवों में आज तक एक बार भी बोट नहीं गयी है. मधेपुरा जिला के रमणी, गंगापुर, भेलाई, रतनपरी, भल्ली, हनुमानपट्टी, रघुनाथपुरा, लक्ष्मीपुर, भित्ताटोल, रहटा, सिकियन, मतनी, गांवों में अभी भी लोग फंसे हैं. अधिकारी बता नहीं पा रहे हैं कि इन्हें कब तक निकाला जाएगा. हालत भयावह है. बहुत सारे लोगों को कई दिनों से खाना नहीं मिला है. इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है लेकिन नियमानुसार न तो आपदा प्रबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक हुई है, न ही राहत-पुनर्वास के लिए दीर्घकालीन नीतियां बनायी गयी हैं.

-ऐसे में आप सरकार को क्या सुझाव देंगी?

मेघा : तटबंध टूटने की घटना की जांच होनी चाहिए. राहत कार्यों में सरकार समाजिक संगठनों की मदद लें. संगठन और सरकार के प्रतिनिधियों की ज्वाईंट कमिटि बननी चाहिए. देश भर के अनेक संगठन मदद के लिए तैयार हैं. वे मदद के लिए हाथ बढा रहे हैं. सरकार को उनका सहायोग स्वीकार करना चाहिए. कोसी और अन्य नदियों में काम करने वाले मल्लाहों को बुलाया जाए. यह जरूरी है. लेकिन साथ ही असामाजिक तत्वों से बचाव के लिए नावों में स्थानीय लोगों को भी रखने की भी व्यवस्था की जाए. रेस्क्यू के लिए जाने वाली बोटों में राहत सामग्री भी हो. सरकार सामाजिक संस्थाओं द्वारा खोले गये सभी शिविरों को बिना हिचकिचाए मदद करे.

इंजीनियर सत्यनारायण ने दी थी चेतावनी

प्रभात कुमार शांडिल्य

कोसी को फिर से भीमनगर बराज में कैद कर रखना, टूटे एफ्लक्स बांध की मरम्मत करना तथा इसके द्वारा एक पखवारे में किये गये विध्वंस की भरपाई अगले ५० वर्षों में संभव नहीं लगती. बाढ़ का पानी उतरने पर स्पष्ट हो जाएगा कि आजादी के ६० वर्षों में जो भी निर्माण कार्य हुआ था, उसे अब पुनर्जीवित करना कितना दुष्कर कार्य है.

इस त्रासदी को किसी ने प्रलय, किसी ने सामूहिक नरसंहार, किसी ने जबरिया जलसमाधि की संज्ञा दी है. किसी ने षड़यंत्र का परिणाम, किसी ने अधिकारियों का निकम्मेपन, किसी ने नेता-अधिकारी-अभियंता-ठेकेदार गठजोड़ के प्रभावी हो जाने का परिणाम बताया है. इधर जो तथ्य प्रकाश में आए हैं. उनसे यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकारी तंत्र के निकम्मेपन के कारण कोसी ने बिहारवासियों पर यह कहर ढाया है.

बिहार सरकार के मुख्य अभियंता सत्यनारायण भीमनगर बैराज के नजद्रीक वीरपुर स्थित कोसी बहुउद्देशीय परियोजना मुख्यालय में पदस्थापित थे. उन्होंने ६ अगस्त,२००८ को ही यह सूचना भेजी थी कि नेपाल में कुसहा के पास एफ्लक्स बांध में तेजी से कटाव हो रहा है और त्वरित कार्रवाई नहीं की गयी तो बांध पर टूट का खतरा है, जिसके भयावह परिणाम होंगे. उन्होंने यह त्राहिमाम संदेश पत्र, फैक्स एवं बेतार संवाद के तौर पर काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में पदास्थापित कोसी परियोजना के बिहार सरकार के लायजन अधिकारी अरुण कुमार सिंह को भेजा. इसी तरह का संदेश बिहार के जल संसाधन विभाग के सचिव सहित कुल ११ अधिकारियों को भेजा, किंतु सब चुपचाप बैठे रहे और बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग १७ अगस्त तक प्रतिदिन प्रेस विज्ञप्ति जारी करता रहा कि राज्य भर के सभी बांध, बैराज और तटबंध पूरी तरह सुरक्षित हैं.

इंजीनियर सत्यनारायण ने त्राहिमाम संदेश में यह कहा था कि कुसहा के बनटप्पू इलाके में जो नेपाल के सुनसरी जिला का भाग है, नदी एफ्लक्स बांध को भयानक रूप से काट रही है और नेपाल के कस्टम विभाग के अधिकारी भारत की ओर से जा रही निर्माण सामग्री से भरे वाहनों को बेवजह काफी देर तक रोक रहे हैं, जिससे मरम्मत संभव नहीं हो पा रही है. साथ ही यह भी शिकायत की थी कि स्थानीय मजदूरों को कटाव में मरम्मत में लगने से रोका और भगाया जा रहा है. इसलिए इसमें भारत और नेपाल सरकार के उच्चाधिकारियों का तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है, ताकि एफ्लक्स को टूटने से बचाया जा सके. काठमांडू स्थित लायजन अफसर अरुण कुमार सिंह से अपेक्षित था कि वे काठमांडू में भारतीय राजदूत तथा नेपाल के विदेश मंत्री मंत्रालय को इन तथ्यों से अवगत कराते, किंतु राज्य सरकार बता रही है कि अरुण कुमार सिंह १८ अगस्त तक छुट्टी पर थे और इन त्राहिमाम संदेशों की सुधी लेने वाला कोई नहीं था. सत्यनारायण ने १४ और १५ अगस्त को भी त्राहिमाम संदेश दोहराया, तिहराया था. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसी कड़ी में काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आधिकारिक प्रवक्ता गोपाल वागले ने कहा है

कि भारतीय दूतावास को बाढ़ की आशंका की जानकारी १७ अगस्त को फैक्स से मिली. वागले और अरुण सिंह, दोनों सत्यनारायण से संदेश मिलने की बात से इंकार करते हैं. इधर सूचना मिली है कि इंजीनियर सत्यनारायण को बतौर सजा डिमोट कर दिया गया है.

यह भी जानकारी मिली है कि कोसी परियोजना के एक सहायक अभियंता वीरपुर स्थित अपने कार्यालय में बैठ कर कनीय अभियंता और लेखपाल के साथ मापी पुस्तिका एवं अन्य अभिलेखों में हेराफेरी करने में १७ अगस्त को मशगूल थे तथा एक प्राइवेट जीप पर कार्यालय से आवास और बाजार की सैर कर रहे थे. सभी अभियंता कोसी परियोजना कॉलोनी, वीरपुर में आराम करते रहे. किसी ने वास्तविक कार्यस्थल पर जाने की जहमत नहीं उठायी.

स्थानीय नेपाली मजदूर बतलाते हैं कि भारतीय ठेकेदार सरकार से ८६ भारतीय रुपये पाते हैं, मजदूरी के मद में और नेपाली मजदूरों से २० रुपये में मजदूरी करवाना चाहते हैं. इसलिए नेपाली मजदूर काम करने को तैयार नहीं हैं. ठेकेदारों और अभियंताओं को मारपीट कर भगाने की बात से वे इंकार करते हैं और कहते हैं कि उनलोगों ने नहीं, उनलोगों के साथ भारतीय अभियंताओं और ठेकेदारों ने बुरा बरताव किया है. लोग मानते हैं कि यह सब नेता-इंजीनियर-ठेकेदार व अफसर गिरोह की करतूत है. इस आशय की खबरें नेपाली के एक प्रमुख दैनिक कांतिपुर टाइम्स में छपी हैं.

राज्य सभा के सदस्य व साहित्य अकादमी से पुरस्कृत लेखक जाबिर हुसेन इस पूरे प्रकरण पर कहते हैं कि कोसी की तबाही से जुड़े जो तथ्य प्रकाश में आये हैं, उनसे लगता है कि राज्य के प्रशासन तंत्र में इस विकराल स्थिति से निपटने का सामर्थ्य नहीं बचा है. ऐसी स्थिति में केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार अधिनियम के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए बचाव एवं राहत की और अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए. साथ ही उन्हें अपनी टीम को अगले कुछ महीने तक प्रभावित इलाकों में ठहर कर काम करने का निर्देश देना चाहिए.

बयानों की बाढ़

१८ अगस्त को नेपाल में कुशहा के पास तटबंध टूटते ही बिहार के सैकड़ों सीमावर्ती गांव तबाह हो गये. हजारों लोग मारे गये. लगभग एक पखबाड़े तक पानी रोज नए-नए इलाकों को डूबोता गंगा की ओर बढ़ता रहा. १६ से ३० अगस्त के बीच जानमाल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ.

आइए जानें, तबाही के इन दिनों में व उसके बाद बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल क्या कह रहे थे.

१६ अगस्त

नेपाल पर आरोप

विजेंद्र यादव, जल संसाधन मंत्री

बिहार के जल संसाधन मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि नेपाल के अधिकारियों के असहयोगात्मक रवैये के कारण तटबंध टूटा है. यह अंतराष्ट्रीय मसला है. भारत सरकार को ही नेपाल से बात करनी चाहिए. फिर भी बिहार सरकार तटबंध कटाव स्थल को पाटने की हर संभव कदम उठा रही है. (दैनिक हिंदुस्तान)

२० अगस्त

नौकरियों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप जारी

ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जदयू

ललन सिंह ने लालू प्रसाद द्वारा नौकरी देने के मामले में नया पिटारा खोलने का ऐलान किया और कहा कि कैसे डीए मामले में पक्ष में गवाही देने वालों को भी नौकरी देकर उपकृत किया गया इसका प्रमाण मीडिया के समक्ष पेश करेंगे. उन्होंने कहा कि जदयू जमीन लिखवाकर रेलवे में नौकरी देने की बात पर अब तक अपनी जगह कायम है. (दैनिक हिंदुस्तान)

श्याम रजक व शकील अहमद खां, प्रवक्ता राजद

राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम रजक व प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शकील अहमद खां ने राजद की ओर से नीतीश कुमार के रेलमंत्रीत्व काल में रेलवे में हुई २३१ नियुक्तियों की सूची जारी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में अपने संसदीय क्षेत्र के एक खास वर्ग के लोगों को और जद यू के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह के चहेतों को रेलवे में नौकरी दी. (दैनिक हिंदुस्तान)

नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि लोकसभा चुनाव में राजद को जीरो पर आउट कर दिया जाएगा. वह मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग में **सहरसा, मधेपुरा** और दरभंगा जिला के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे.

२१ अगस्त,

देर आये, तब भी दुरुस्त नहीं

राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष

प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने कहा कि नेपाल स्थित कुसहा के पास कोसी तटबंध टूटने के बाद भीमनगर बराज के सभी फाटक खोल दिये गये जिससे हजरों लोग बह गये. बराज का फाटक खोलने से पहले लोगों को सूचना तक नहीं दी गयी. अगर सरकार सजग रहती तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था और हजारों लोग मौत के मुंह में जाने से बच सकते थे.उन्होंने बाढ़ से प्रभावित जिलों को सेना के हवाले करने और सेना से राहत कार्य चलाने मांग की. (दैनिक हिंदुस्तान)

{तथ्य यह है कि भीमनगर बराज से काफी पहले नेपाल में स्थित कुसहा के पास तटबंध टूटा है. जहां से तटबंध टूटा है वहां कोसी की नयी धार बन गयी है. इसी से होकर कोसी का लगभग ८० फीसदी पानी बह रहा है. कोसी अंचल के हजारों लोगों की मौत बराज से पानी छोड़ने से नहीं बल्कि तटबंध टूटने से हुई थी. राबड़ी देवी के इस बयान को आधार बना कर जलसंसाधन मंत्री विजेंद्र यादव ने अगले दिन कहा कि राबड़ी देवी को बिहार के भूगोल का ज्ञान नही है. आगे चलकर राजद की ओर से पूर्व जल संसाधन मंत्री जगदानंद ने मोर्चा संभाला तो उन्होंने भी शुरूआत एक उलझे हुए बयान (प्रभात खबर, २३ अगस्त) से की, जिस कारण उनके सवालों का कोई उत्तर न होने के बावजूद सत्ता पक्ष उन्हें पहले बयान के आधार पर आड़े हाथों लेता रहा.}

२२ अगस्त

जयप्रकाश-विजेंद्र आमने सामने

राजद के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद कहा कि नेपाल स्थित कोसी तटबंध टूटने से प्रलय की स्थिति है. उन्होंने कहा कि केंद्र के अनवरत निर्देश के बावजूद कार्यों की कोई जानकारी नहीं दी गयी. कोसी तटबंध के मरम्मत के लिए राशि केंद्र सरकार देती है.राशि खत्म भी नहीं हुई, काम भी नहीं हुआ और कहा गया कि कार्य पूरा हो गया है.

श्री यादव के आरोपों का जबाव देते हुए बिहार के जल संसाधन मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को अंतरराष्ट्रीय कानून का ज्ञान नहीं है. नेपाल क्षेत्र में कोसी का तटबंध टूटा नहीं बल्कि कटाव हुआ है. केंद्रीय मंत्री को किस हैसियत से नेपाल क्षेत्र में तटबंध कटाव की सूचना दी जाती. क्या इनका वहां के दूतावास पर नियंत्रण है? (दैनिक जागरण)

२२, २३, २४ व २५ अगस्त

नौकरी मामले में एक-दसरे को बदनाम करने की होड़

श्याम रजक व शकील अहमद खां, अखिलेश सिंह (राजद)

ललन व शिवानंद तिवारी (जदयू)

२२ अगस्त : जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह व राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने संवाददाता सम्मेलन में ऐसे चार लोगों की विवरणी पेश की जिन्हें डीए मामले में रेलवे में नौकरी मिली. उन्होंने कहा कि पार्टी इन सब मामलों को लेकर २३ अगस्त को प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगी और उनके समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करेगी.

२२ अगस्त : राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम रजक ने कहा है कि जदयू के नेता डिरेल्ड हो गये हैं इसलिए रेल मंत्री लालू प्रसाद पर आरोप लगा रहे हैं. श्री प्रसाद अदालत में गवाही के बाद रेल मंत्री बने थे लिहाजा यह कहना पूरी तरह गलत है कि किसी को गवाही के बदले रेलवे में नौकरी की पेशकश की गयी.

२३ अगस्त : राजद नेता व केंद्रीय मंत्री डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता श्याम रजक, राज्य प्रवक्ता शकील अहमद खां एवं महासचिव निहोरा प्रसाद यादव ने आरोपों का दूसरा ऐपिसोड जारी करते हुए नीतीश कुमार पर रेलवे के ग्रुप-सी के पद पर नियुक्ति में हेरा-फेरी का आरोप लगाते हुए नौकरी पाये नालंदा एवं बेगुसराय संसदीय क्षेत्र के १०० से ज्यादा लोगों का नाम पेश किया. उन्होंने कहा राजद का प्रतिनिधिमंडल जल्दी ही प्रधानमंत्री से मिलकर मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करेगा.

२३ अगस्त : जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह ने राजद द्वारा प्रधानमंत्री से जांच की मांग को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि लालू प्रसाद जानते हैं कि जांच में कुछ नहीं मिलने वाला इसलिए वे खुद जांच से कतरा रहे हैं, सिर्फ बयान देकर काम चला रहे हैं.

२४ अगस्त : जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि रेलवे भर्ती मामले में राजद ने बेगुसराय, नालंदा और बाढ़ के लोगों की मेधा पर सवाल उठाया है. परोक्ष रूप से **दो खास समुदायों** के लोगों की मेहनत, श्रम और अध्ययन साधना पर प्रश्न खड़ा किया गया है. उन्होंने राजद के इस कृत्य की भर्त्सना की. (दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान)

२४ अगस्त (प्रधानमंत्री से राजग नेताओं की मुलाकात) : राजग का एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार (२३ अगस्त) को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भेंट कर जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले के मामले में रेलमंत्री लालू प्रसाद को तुरंत बर्खास्त कर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की. जदयू के अध्यक्ष शरद यादव, भाजपा के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में प्रधानमंत्री से मिला और उसने श्री यादव व उनके परिवार वालों के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े दस्तावेज और ज्ञापन दिया. २५ मिनट की इस मुलाकात के बाद श्री नकवी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री इन दस्तावेजों के बावजूद रेल मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो यही माना जाएगा कि उनकी मूक सहमति है. (दैनिक हिंदुस्तान)

२४ अगस्त : रेल मंत्री लालू प्रसाद ने एनडीए के जमीन के बदले नौकरी देने के आरोपों को नीचता की हद बताते हुए विद्वेष व प्रतिशोध की भावना किया हुआ काम करार दिया. श्री प्रसाद ने कहा कि यह एनडीए की विदाई का समय है. (दैनिक हिंदुस्तान)

२५ अगस्त

यह प्रलय है, पीड़ितों के परिजन आगे आएं !

नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार सरकार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार (२४ अगस्त) को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के बाद खुद स्वीकार किया कि बाढ़ नहीं प्रलय की चेतावनी है. मुख्यमंत्री ने लोगों से सचेत रहने को कहा. उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री से भी बाढ़ की विभीषिका व तबाही पर चर्चा करेंगे. पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्तर पर गंभीर है और स्थिति सामान्य होने तक राहत कार्य चलता

रहेगा. उन्होंने गैर सरकारी संगठनों से भी मदद मांगी. इसके अलावा लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए पीड़ित परिवार के परिजनों को आगे आने की अपील की. (दैनिक हिंदुस्तान, पृष्ठ सं.-१ व २)

२६ अगस्त

नेपाल में भी करेंगे राहत कार्य

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वे नेपाल में भी राहत कार्य चलाने को तैयार हैं. सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र अगर यह जिम्मेवारी उन्हें देगा तो वे बखूबी उसपर अमल करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों को सीमा या राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। इस समय हम सभी को मिलकर राहत कार्य चलाना है, लोगों की मदद करनी है. कोसी नदी द्वारा फैलाई गई तबाही का दंश बिहार के साथ-साथ नेपाल में भी लोग भुगत रहे हैं. लिहाजा बिहार हर तरह की जिम्मेवारी उठाने को तैयार है. (दैनिक हिंदुस्तान)

पूर्व जल संसाधन मंत्री के सवालों पर भिड़ंत

धारा बदलने से आयी बाढ़ : जगदानन्द

राजद के वरिष्ठ नेता व पूर्व जल संसाधन मंत्री जगदानन्द ने कोसी तटबंध के टूटने से आई बाढ़ पर राजनीति न करने की सलाह पक्ष और विपक्ष को दी है. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में कोई राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ तो इससे नेपाल को राजनीतिक ताकत मिल जाएगी. पूर्व मंत्री ने कहा कि कुसहा में बांध टूटा नहीं है बल्कि यह बाढ़ कोसी की धारा बदलने का परिणाम है. **(२३ अगस्त, ०८, प्रभात खबर)**

निजी दुश्मनी से आयी बाढ़

पूर्व जल संसाधन मंत्री जगदानन्द ने बांध टूटने का कारण गिनाते हुए कहा कि मुख्मंत्री ने निजी दुश्मनी दिखाते हुए मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया एवं पूर्णिया जिले को इस हाल में पहुंचा दिया है. उन्होंने विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम २१ अगस्त को लिखा पत्र भी सार्वजनिक किया. श्री सिंह ने सिंचाई विभाग की बाढ़ बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि १७ अगस्त तक विभाग बताता रहा कि सभी तटबंध सुरक्षित हैं. १८ को दोपहर में तटबंध टूटने के बाद कहा गया कि तटबंध के १२.१० एवं १२.९० किमी. के स्परों पर कई दिनों से नदी का कटाव हो रहा था. फलस्वरूप ४०० मी. की लंबाई में तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे नेपाली भूभाग एवं वीरपुर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है. उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल किया कि सिंचाई विभाग का लाइजनिंग ऑफिसर का स्थाई कार्यालय काठमांडू में है, उसने बांध मरम्मत को लेकर नेपाल स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क क्यों नहीं किया? (३० अगस्त, दैनिक हिंदुस्तान)

नदारद थे अभियंता

पूर्व जल संसाधन मंत्री जगदानन्द ने कहा कि बांध तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं और उनमें गैरत है तो शीघ्र गद्दी छोड़ें. अपनी ताकत का अहसास कराने और नरमेघ करने के लिए नीतीश कुमार ने बांध तोड़ा है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यह कहकर लोगों को बरगलाया जा रहा है कि कोसी उच्चस्तरीय कमेटि केन्द्र की कमेटि है. दरअसल बिहार सरकार द्वारा गठित इस कमेटि में राज्य और केन्द्र के विशेषज्ञों की

अध्यक्षता केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष करता है. उन्होंने अक्टूबर २००७ में आयोजित इस कमेटि की बैठक की कॉपी पेश करते हुए कहा कि इस बैठक में सूबे के जलसंसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख समेत एक को छोड़कर सभी मुख्य अभियंता नदारद थे. इससे अहसास लग सकता है कि कोसी बांध की सुरक्षा को लेकर नीतीश कुमार कितने गंभीर थे. (३१ अगस्त, ०८, दैनिक हिंदुस्तान)

केन्द्र ने नहीं की कार्रवाई : विजेन्द्र यादव

जलसंसाधन मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा है कि तटबंध मरम्मत से बचाव कार्यों तक में केन्द्र के असहयोग के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई. जहां तटबंध की मरम्मत के लिए केन्द्रीय कमिटी ने मामूली राशि स्वीकृत की, वहीं कटाव शुरू होने के बाद केन्द्रीय एजेंसियों से बार-बार गुहार लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. कोसी का तटबंध अंतरराष्ट्रीय मसला होने के कारण केन्द्र के अधीन है तटबंध का कटाव निरोधक कार्य कोसी उच्चस्तरीय कमेटि द्वारा अनुसंशित होता है. इसके अध्यक्ष केन्द्र सरकार के अधिकारी होते हैं. राज्य उन अनुसंशाओं के अनुरूप काम करवाने को बाध्य हैं. जहां तटबंध कटा है वहां कमेटि ने महज १.२५ लाख रुपये के कार्यों की ही अनुसंशा की. यह कार्य १५ जून के पूर्व करा लिया गया और इसे १८ जूलाई की बैठक में केन्द्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने भी स्वीकारा की निर्धारित काम पूरा हुआ है. अगर केन्द्रीय जलसंसाधन मंत्रालय को राज्य सरकार द्वारा कटाव निरोध कार्य से संतुष्टि नहीं थी तो उसने अपने स्तर से ही नेपाल के हिस्से के कार्यों का कार्यान्वयन क्यों नहीं करवाया? (३१ अगस्त, ०८, दैनिक हिंदुस्तान)

राजद को कैसे मिला पत्र?

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह एवं सिंचाई मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा है कि कोसी तटबंध टूटने की निष्पक्ष जांच कराने पर केंद्र ही कटघरे में खड़ा होगा. श्री सिंह ने पूछा कि विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी का पत्र राजद के पास कैसे पहुंच गया? उन्होंने कहा कि जगदानन्द अज्ञानी की तरह बात कर रहे हैं. उनके शासनकाल में २००४ में बिहार के सारे तटबंध टूट गएं थे. वे कैसे टूटे? दूसरी ओर जदयू के प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि लालू प्रसाद जब भी राहत कार्य में जुटते हैं, घोटाला हो जाता है. उन्होंने कहा कि रेलवे के ६० करोड़ रुपये लेकर जो राहत कार्य वे करना चाहते हैं उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवा दें. उन्होंने पूर्व सिंचाई मंत्री जगदानन्द पर बरसते हुए कहा कि वे सच को झूठ और झूठ को सच बनाने के महारथी हैं. अपने पहले बयान में कहा कि तटबंध की टूट मानवीय भूल नहीं है बल्कि परिस्थितियों की देन है. इससे लड़ने के लिए सामूहिक प्रयास होने चाहिए न कि राजनीति. अचानक अब पलटी मार कर कह रहे हैं कि बांध नीतीश कुमार ने तोड़ा है. (१ सितंबर, ०८, दैनिक हिंदुस्तान)

भाई की पीड़ा से हुई बेचैनी : शिवानन्द

जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानन्द तिवारी ने रेल मंत्री लालू प्रसाद की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सक्रियता पर सवाल करते हुए कहा कि पिछले साल आयी बाढ़ के दौरान वे कहां थे? लोग कह रहे हैं कि 'भाई का दर्द भाई ही समझता है'. भाई की पीड़ा ने उन्हें इतना संवेदनशील बना दिया है कि वे उनके बीच कूद पड़े हैं. (२ सितंबर, ०८, दैनिक जागरण)

नीतीश के अहंकार ने डूबोया : लालू

रेल मंत्री लालू प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने अहंकार में पूरे बिहार को डूबो दिया. उन्होंने कहा कि कोसी के प्रलय के लिए नीतीश सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं. यह क्रिमिनल ऐक्ट है. सी.एम. होके छोटी बात करते हैं. कहते हैं-'चुनाव के चलते राहत बंटवाया जा रहा है.' 'भाई का दर्द भाई ने जाना.' पटना में बैठ के कंप्यूटर मे राहत संभव नहीं. सरकार में बैठे लोगों का दिमाग खराब हो गया है. कह रहे हैं 'राहत रेल' को पटना नहीं आने देंगे. बाल ठाकरे की तरह बयान दे रहे हैं कि पटना में शिविर नहीं है. (३ सितंबर, ०८, दैनिक हिंदुस्तान)

बहस नहीं करना है : नीतीश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनको किसी के साथ बहस में शामिल नहीं होना है. उनको तो बस बाढ़ पीड़ितों के लिए काम करना है. रेलमंत्री लालू प्रसाद द्वारा उठाये जा रहे सवालों के बाबत उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को आदत है ४८ घंटे घूमकर ४८ बार मीडिया से बात करने की. ३ साल पहले जनता ने उनको ऐसा उखाड़ कर फेंका है कि वह इसे पचा नहीं पा रहे हैं. बाढ़ पीड़ितों द्वारा घर छोड़कर भागने की तुलना देश के बंटवारे से किये जाने से नाराज श्री कुमार ने कहा कि इससे बड़ी नासमझी क्या हो सकती है? पूर्णिया के चूनापूर हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री ने लालू प्रसाद के दौरे को ड्रामेबाजी की संज्ञा दी. (३ सितंबर, ०८, दैनिक हिंदुस्तान)

इन्ही की करनी से टूटा तटबंध : मोदी

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हीं दलों की करनी से कोसी का तटबंध टूटा है. उन्होंने तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि आज भी कोसी तटबंध की वही स्थिति है जो १९९१ में थी लेकिन राजद और कांग्रेस की हुकूमत ने इस पर ध्यान नहीं दिया. श्री मोदी ने तत्कालीन सिंचाई मंत्री जगदानंद सिंह को ईमानदार और सक्षम तो माना लेकिन यह भी कहा कि वे जबान के अच्छे नहीं हैं. (६ सितंबर, ०८, दैनिक हिंदुस्तान)

काठमांडू कार्यालय को नहीं मिला पैसा : जगदानन्द

पूर्व जल संसाधन मंत्री राजद नेता जगदानन्द ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरसते हुए कहा कि जनता के बीच भ्रम उत्पन्न करने के लिए कुसहा के समीप कोसी तटबंध के १२.९० किमी. टुटान की चर्चा नहीं कर इधर-उधर की पुरानी कहानी सुनायी जा रही है. सरकार जिस काठमांडू स्थित जल संसाधन विभाग के लिए संपर्क अधिकारी के माध्यम से सूचना देने की बात करती है वह कार्यालय ही आवंटन के अभाव में बंद है. उन्होंने कहा कि तटबंध को लेकर सरकार का तर्क है कि नेपाल क्षेत्र में कार्य नहीं करने दिया गया जबकि वह खुद मानती है कि जून में सभी कार्य पूरे कर लिए गए. आखिर ऐसी कौन स्थिति उत्पन्न हो गयी कि मात्र ५ अगस्त से ही रहे कटाव रोकने के कार्य में ही व्यवधान उत्पन्न हो गया. एकमात्र जल संसाधन विभाग ही ऐसा विभाग है जिसने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के लिए काठमांडू में कार्यालय खोल रखा है. इसको वर्तमान सरकार ने बंद करवा दिया है. कार्यालय व्यय व कर्मियों के वेतन भुगतान आदि के लिए सरकार ने आवंटन बंद कर दिया है. इसको प्राप्त करने को संपर्क पदाधिकारी अरुण कुमार १४ व १५ को सिंचाई भवन मुख्यालय पहुंचे थे. इनको अब छुट्टी पर दिखाया जा रहा है. सरकार बताये कि ऐसी विषम परिस्थिति में किस आधार पर छुट्टी मंजूर की गयी. संपर्क कार्यालय का फैक्स

व फोन भी भुगतान नहीं होने के कारण बंद है. उन्होंने कहा कि सरकार बताये कि किस परिस्थिति में संपर्क पदाधिकारी मुख्यालय में मौजूद थे. उन्होंने कहा कि वीरपुर के तत्कालीन मुख्य अभियंता सत्यनारायण ने तो मुख्यालय सहित सात स्थानों पर स्थिति की सूचना दी किंतु उस पर ध्यान नहीं दिया गया. उनका पत्र ही असलियत को सामने रख रहा है. जनता को मालूम हो गया कि सरकार सोयी रही व मामले को अभियंताओं पर छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि विभाग के वीरपुर स्थिति हवाई अड्डे का भी कटाव रोकने को कभी उपयोग नहीं किया गया. (८ सितंबर, ०८, दैनिक जागरण)

(**कुछ छूट गए प्रसंग :** तबाही के इन दिनों में ही राज्य सरकार ने राकंपा के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा का मकान खाली करवाया. राजनीतिक बवाल खड़ा होने पर कई दिनों तक राज्य सरकार के मंत्री समेत जदयू के अनेक वरिष्ठ नेता इस पर प्रेस कांफ्रेंस करते रहे. लोजपा के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने बाढ़ के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी से लगभग परहेज रखा. माले बाढ़ के शरूआती दिनों में राज्य व केन्द्र सरकार की 'साम्राज्यवादपरस्ती' के खिलाफ जेल भरती रही. माकपा और भाकपा ने बयानबाजी को लेकर खास उत्साह नहीं दिखाया.)

सुधरो नीतीश कुमार

सत्यकाम

आज से ठीक दस साल पहले अगस्त १९९९ में जब गाइसल में ट्रेन हादसा हुआ था, तब के रेल मंत्री नीतीश कुमार ने नैतिकता की दुहाई देकर मंत्री पद से इस्तीफा कर दिया था. उस वक्त केंद्र में-एक ऐसी सरकार थी, जिसने विश्वास मत खो दिया था. और जिसके मुखिया राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप चुके थे. चुनाव संपन्न होने और नयी सरकार के गठन तक-जैसी परंपरा है-राष्ट्रपति ने वाजपेयी जी को सरकार में रहने को कहा था. ऐसी सरकार कामकाजी सरकार कही जाती है, और इससे इस्तीफा देने का कोई मतलब नहीं होता. मुहावरे में इसे उंगली खुरच कर शहादत देना कहा जा सकता है.यह नौटंकी नीतीश कुमार ने की थी. उस पर तुर्रा यह था कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, इसलिए मेरे त्याग को नहीं समझा गया. वे अपनों के बीच फुनफुनाते थे कि मैं यदि उंची जाति का होता तो मुझ पर संपादकीय लिखे जाते. नीतीश कुमार ऐसी आत्ममुग्धता में अक्सर डूबे होते हैं. वे खुद परीक्षार्थी और खुद ही परीक्षक होते हैं. पिछले तीन साल से अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड खुद जारी कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं.

लेकिन अबकी इस बाढ़ अथवा जलप्लावन ने उनकी ऐसी की तैसी कर दी है. जाने अब उनकी नैतिकता इस्तीफा की सिफारिश कर रही है या नहीं. गाइसल में पटरी टूटी थी, किसी शरारत के कारण. अबकी तटबंध टूटा है, सरकार की गैर जबावदेही के कारण. तब कुछ सौ लोग तबाह हुए थे, अबकि लाखों लोग तबाह हुए हैं.

मैं नहीं जानता नीतीश कुमार के मन में इस्तीफा की बात उठ रही है या नहीं. विपक्ष चाहेगा कि वो इस्तीफा कर दें ताकि उनके लिए मार्ग प्रशस्त हो जाए. ऐसी बाढ़ देख कर उनके हाथों में खुजली हो रही होगी. लेकिन इन पंक्तियों का लेखक ऐसा नहीं चाहेगा. नीतीश कुमार को ऐसी बातें मन से निकाल देनी चाहिए और राजधर्म का पालन करना चाहिए.

लेकिन काश नीतीश कुमार राजधर्म का पालन करते. जिस मंसूबे से राज्य की जनता उन्हें सरकार में लायी थी-उसके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं नीतीश कुमार. उन्हें फुरसत निकाल कर अपनी स्थिति का आकलन करना चाहिए.

यह बाढ़, जिसे नीतीश कुमार प्रलय कह रहे हैं, की स्थिति क्या एक दिन में बनी है-अचानक बनी है? नहीं! यह हादसा नहीं है. यह राज्य सरकार की नाकामियों का कुफल है. इसे मुख्यमंत्री स्वीकारें. नहीं स्वीकारेंगे तो इसका निराकरण भी नहीं कर पायेंगे.

जरा देखिए कि तटबंध जब दरकनें ले रहा था तो नीतीश कुमार और उनके लोग क्या कर रहे थे. इनके दो प्रिय पालतू इस दरम्यान एक केंद्रीय मंत्री की जमीन-जायदाद की नाप-जोख कर रहे थे. मुख्यमंत्री का पूरा सचिवालय उनके लिए मीडिया-मसाला तैयार करने में लगा था. पखवारे भर के उन भाषणों के क्लीप

देखिए जिसे नीतीश कुमार धुंआधार दे रहे थे. वे लालू को जीरो पर आउट कर रहे थे. पूरे बिहार में उनकी ध्वजा फहरा रही थी. उनके चापलूस उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहे थे. पता नहीं क्या-क्या बना रहे थे.

बांध १८ तारीख को टूटता है. नीतीश की खुमारी २४ तारीख को टूटती है. चिल्लाते हैं- जा रे, यह तो प्रलय है. नीतीश कुमार! देखा! चपलूसों ने आपको कहां पहुंचा दिया. छोडिये प्रधानमंत्री की कुर्सी. मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बचाइये. और छोडिये मुख्यमंत्री-तंत्री की कुर्सी-अपने ही आत्मधिक्कार के दलदल से तो खुद को निकालिए. हजारों लोग बाढ़ से निकल कर सुरक्षित स्थानों पर आ रहे हैं. आप भी उस जानलेवा बाढ़ से निकलिये जिसमें गरदन तक डूब चुके हैं. आपके इर्द-गिर्द सांप-बिच्छुओं और लाशों का ढेर लग गया है. इनके बीच से निकलिये. केवल जनता को ही मत बचाइये-खुद भी बचिये.

तरस आती है नीतीश कुमार आप पर. जिस अरमान से जनता आपको लायी थी, उसके अरमानों को चूर-चूर कर दिया. दुनिया भर के लंपट, चापलूस अपने इर्द-गिर्द जुटा लिये. कोई मुकदमेबाज है तो कोई छूरेबाज, कोई जालसाज है तो कोई कोयला-किरासन माफिया. ऐसे ही लोग आपके चरगट्टे के स्थायी सदस्य हैं. इनके साथ ही रोज आपका उठना-बैठना होता है. आपका मंत्रीपरिषद संदिग्ध आचरण वालों का जमावड़ा है. सबसे नालायक अधिकारियों को आपने अपने इर्द-गिर्द जमा कर रखा है. क्योंकि अफसर चुनने में जाति आपकी कसौटी होती है. नवंबर आ रहा है और आप फिर रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिएगा. आप से मेरा निवेदन होगा कि एक बार ईमानदार भाव से लालू के तीन साल से अपने इस तीन साल को तौलिये. वह आदमी, जिसे प्रायः नॉन सीरियस और जोकर तक कहा गया, बिहार के मुख्यमंत्री की कुरसी पर बैठने के तीसरे साल में गरीबों-पिछडों का मसीहा बन गया था. उनका पतन तो तब शुरू हुआ जब दंभ उन पर हावी हो गया और अपने काबिल साथियों को नजरअंदाज कर वो चापलूस और लंपट तत्वों से घिरने लगे. लेकिन आपने तो मुख्यमंत्री की कुरसी पर बैठते ही चापलूसों और लंपटों के हाथों अपने को सौंप दिया. और इसका नतीजा है कि एक नायक वाली आपकी जो छवि मुख्यमंत्री पद पाते वक्त थी वह आज कुसहा बांध की तरह ध्वस्त हो चुकी है. लेकिन इतने पर भी बिहार की जनता आप से नाउम्मीद नहीं हुई है. वह आपसे आज भी-अब भी उम्मीद करेगी कि चपंडुकों के चरगट्टे से आप बाहर निकलेंगे और अपने हृदय पर हाथ रख कर अपनी ही धड़कनों को सुनेंगे. यदि ऐसा आपने किया तो विश्वास मानिये, हर धड़कन से यही स्वर उभरेगा-सुधरो नीतीश कुमार, सुधरो. खुदा के लिए सुधरो. बिहार के लिए सुधरो.

अन्न पचीसी के दोहे

नागार्जुन

सीधे सादे शब्द हैं, भाव बड़े ही गूढ़
अन्न पचीसी घोख ले, अर्थ जान ले मूढ़

कबिरा खड़ा बजार में, लिया लुकाठी हाथ
बंदा क्या घबराएगा, जनता देगी साथ

छीन सके तो छीन ले, लूट सके तो लूट
मिल सकती कैसे भला, अन्न चोर को छूट

आज गहन है भूख का धुंधला है आकाश
कल अपनी सरकार का होगा पर्दाफाश

नागार्जुन-मुख से कढ़े साखी के ये बोल
साथी को समझाइए रचना है अनमोल

अन्न पचीसी मुख्तसर, लोग करोड़ करोड़
सचमुच ही लग जाएगी आंख कान में होड़

अन्नब्रह्म ही ब्रह्म है बाकी ब्रह्म पिशाच
औघड़ मैथिल नागजी अर्जुन यही उवाच

बाढ २००८

अनकही कहानी

'फ्री थिंकर्स'

कुम्हरार, पटना-800026

e-mail : gramprivesh@gmail.com

मुद्रक : न्यू फाइन आर्ट ऑफसेट, मुसल्लहपुर हाट रोड, पटना-६